

# अर्थव्यवस्था की स्थिति और संभावना

# 1

## अध्याय

हालांकि भारत के हालिया अवमंदन के मूलभूत कारण अंशतः विदेशी हैं, घरेलू कारण भी महत्वपूर्ण हैं। सशक्त पश्च-वित्तीय-संकट अभिप्रेरक के परिणामस्वरूप वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में अपेक्षाकृत सुदृढ़ वृद्धि हुई। फिर भी आपूर्ति पक्ष बाधाओं के साथ युग्मित खपत को बढ़ावा दिए जाने के कारण मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। मौद्रिक नीति को कठोर किया गया है जबकि वृद्धि के लिए बाह्य आघातों में वृद्धि हुई। परिणामी अवमंदन विशेषकर वर्ष 2012-13 में सर्वत्र परिलक्षित हुआ जिससे अर्थव्यवस्था का कोई क्षेत्र अछूता नहीं बचा। सकल निवेश में समनुरूप गिरावट के बिना कम होती बचतें चालू खाता घाटा (सीएडी) के व्यापक होने में परिणामी हुई। हालिया महीनों में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआर) भी कम हो रहा है। तथापि, एक लघु अवमंदन के पश्चात् खाद्य मुद्रास्फीति का समग्र मुद्रास्फीति से उच्चतर बना रहना जारी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआर) में खाद्य के उच्चतर भारांश को देखते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति लगभग द्विअंकीय बनी रही है। अवमंदन का एक और परिणाम कर तथा कर भिन्न राजस्वों का लक्ष्यों से अपेक्षाकृत कम होना है। आर्थिक व्यय, विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों के व्यय के बढ़ने से यह खतरा, कि राजकोषीय लक्ष्यों का अत्यधिक उल्लंघन हो जाएगा, वर्तमान वर्ष में अत्यधिक यथार्थ हो गया है। इस स्थिति के मद्देनजर सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के लिए तात्कालिक कदम उठाना अत्यधिक आवश्यक हो गया था ताकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही आपूर्ति की सहजता को बहाल करने के लिए कारपोरेट एवं अवसंरचना निवेश को सुकर बनाने के लिए उपाय किया जाना भी आवश्यक था। हालिया महीनों में घोषित अनेक उपाय सरकार की राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने तथा वृद्धि दर को बढ़ाने के साथ-साथ सीएडी को कम करने की ओर लक्षित हैं। वर्ष 2013 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुछ-कुछ सुधार होने की संभावना के साथ ये उपाय वर्ष 2013-14 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को सुधारने में अवश्य सहायक होंगे।

## स.घ.उ. की वृद्धि तथा अन्य वृहद् सकल घटक

1.2 वैश्विक वित्तीय संकट द्वारा वर्ष 2008-09 में अभिप्रेरित मंदी के पश्चात् भारतीय अर्थव्यवस्था ने राजकोषीय तथा मौद्रिक अभिप्रेरण के प्रति सशक्त अभिक्रिया दर्शाई तथा वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में क्रमशः 8.6 प्रतिशत और 9.3 प्रतिशत की संवृद्धि दर हासिल की (सारणी 1.1) तथापि, अर्थव्यवस्था द्वारा मुद्रास्फीतिकारी रुझान प्रदर्शित किए जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2010 में नीतिगत दरें बढ़ानी आरम्भ कर दी। उच्च दरों के साथ साथ नीतिगत बाधाओं ने निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाला

तथा अनुवर्ती दो वर्षों अर्थात् 2011-12 तथा 2012-13 में, वृद्धि दर धीमी हो कर क्रमशः 6.2 प्रतिशत तथा 5.0 प्रतिशत हो गई। तथापि, इस अवमंदन के बावजूद, 2012-13 के वर्ष से समाप्त होने वाले दशक में घटक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 7.9 प्रतिशत रही।

1.3 संवृद्धि में कमी का प्रमुख कारण उद्योग (जिसमें खनन तथा उत्खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस तथा जलापूर्ति और निर्माण क्षेत्र शामिल है) का कमजोर होना है जिसने वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 में क्रमशः केवल 3.5 प्रतिशत तथा 3.1 प्रतिशत की

**0.1 मुख्य संकेतक**

आंकड़ा श्रेणियां और संघटक	यूनिट	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
<b>1. स.घ.उ. और संबंधित संकेतक</b>							
स.घ.उ. (वर्तमान बाजार मूल्य)	₹ करोड़	4987090	5630063	6477827	7795313 <sup>द्वि.सं.अ.</sup>	8974947 <sup>प्र.सं.अ.</sup>	100,28,118 <sup>अ.अ.</sup>
वृद्धि दर	%	16.1	12.9	15.1	20.3	15.1	11.7
स.घ.उ. (घटक लागत 2004-05 के मूल्य पर)	₹ करोड़	3896636	4158676	4516071	4937006 <sup>द्वि.सं.अ.</sup>	5243582 <sup>प्र.सं.अ.</sup>	5503476 <sup>अ.अ.</sup>
वृद्धि दर	%	9.3	6.7	8.6	9.3	6.2	5.0
बचत दर	स.घ.उ. का %	36.8	32.0	33.7	34.0	30.8	उ.न.
पूँजी निर्माण (दर)	स.घ.उ. का %	38.1	34.3	36.5	36.8	35.0	उ.न.
प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (मौजूदा कीमतों पर उपादान लागत)	₹	35825	40775	46249	54151	61564	68747
<b>2. उत्पादन</b>							
खाद्यान्न	मिलियन टन	230.8	234.5	218.1	244.5	259.3	250.1 <sup>क</sup>
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक <sup>ख</sup> (वृद्धि)	प्रतिशत	15.5	2.5	5.3	8.2	2.9	0.7 <sup>ग</sup>
विद्युत उत्पादन (वृद्धि)	प्रतिशत	6.3	2.7	6.6	5.5	8.1	4.6 <sup>ग</sup>
<b>3. कीमतें</b>							
मुद्रास्फीति (थो.मू.सू.) (12 माह औसत)	% परिवर्तन	4.7	8.1	3.8	9.6	8.9	7.6 <sup>घ</sup>
मुद्रास्फीति सीपीआई (आई डब्ल्यू) (औसत)	% परिवर्तन	6.2	9.1	12.4	10.4	8.4	10.0 <sup>घ</sup>
<b>4. वैदेशिक क्षेत्र</b>							
निर्यात वृद्धि (अमरीकी डालर)	% प्रतिशत	29.0	13.6	-3.5	40.5	21.3	-4.9 <sup>घ</sup>
आयात वृद्धि (अमरीकी डालर)	% प्रतिशत	35.5	20.7	-5.0	28.2	32.3	-0.0 <sup>घ</sup>
चालू खाता शेष (सीएबी)/स.घ.उ.	प्रतिशत	-1.3	-2.3	-2.8	-2.8	-4.2	-4.6 <sup>घ</sup>
विदेशी मुद्रा भण्डार	बिलियन अमरीकी डालर	309.7	252.0	279.1	304.8	294.4	295.5 <sup>घ</sup>
औसत विनिमय दर	₹/अमरीकी डालर	40.26	45.99	47.44	45.56	47.92	54.47 <sup>घ</sup>
<b>5. मुद्रा तथा ऋण</b>							
स्थूल मुद्रा (एम 3) (वार्षिक)	% परिवर्तन	21.4	19.3	16.8	16.0	15.6	11.2 <sup>घ</sup>
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ऋण (वृद्धि)	% परिवर्तन	22.3	17.5	16.9	21.5	15.9	15.1 <sup>घ</sup>
<b>6. राजकोषीय संकेतक (केन्द्र)</b>							
सकल राजकोषीय घाटा	स.घ.उ. का %	2.5	6.0	6.5	4.8	5.7 <sup>अ</sup>	5.1 <sup>अ</sup>
राजस्व घाटा	स.घ.उ. का %	1.1	4.5	5.2	3.2	4.3 <sup>अ</sup>	3.5 <sup>अ</sup>
प्राथमिक घाटा	स.घ.उ. का %	-0.9	2.6	3.2	1.8	2.6 <sup>अ</sup>	1.9 <sup>अ</sup>
<b>7. जनसंख्या</b>							
	मिलियन	1138	1154	1170	1210 <sup>द</sup>	उ.न.	उ.न.

प्र.सं.अ.: प्रथम संशोधित अनुमान; द्वि.सं.अ.: द्वितीय संशोधित अनुमान; अ.:अग्रिम अनुमान त्व.अ. त्वरित अनुमान

उ.न.: उपलब्ध नहीं

क द्वितीय अग्रिम अनुमान

ख औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष (2004-05=100) पर 2005-06 से संशोधित किए गए हैं।

ग अप्रैल-दिसम्बर 2012

घ 2012-13 (अप्रैल-जनवरी)

ड स.घ.उ. के प्रति सीएबी अनुपात, अप्रैल-सितम्बर 2012 की अवधि के लिए है;

च जनवरी 2013 के अंत में

छ 2012-13 के लिए औसत विनिमय दर (अप्रैल 2012-जनवरी 2013)

ज अनंतिम (28 दिसम्बर 2012 तक)

झ 2011-12 के लिए राजकोषीय संकेतक अनंतिम वास्तविक आंकड़ों (अलेखापरीक्षित) पर आधारित हैं।

ञ बजट अनुमान

ट जनगणना

सारणी 1.1 : 2004-2005 कीमतों पर घटक लागत पर स.घ.उ. में वृद्धि ( प्रतिशत )								
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 <sup>अ.अ.</sup>	2010-11 <sup>अ.अ.</sup>	2011-12 <sup>अ.अ.</sup>	2012-13 <sup>अ.अ.</sup>
कृषि, वानिकी एवं मात्स्यिकी	5.1	4.2	5.8	0.1	0.8	7.9	3.6	1.8
खनन तथा उत्खनन	1.3	7.5	3.7	2.1	5.9	4.9	-0.6	0.4
विनिर्माण	10.1	14.3	10.3	4.3	11.3	9.7	2.7	1.9
बिजली, गैस तथा जलापूर्ति	7.1	9.3	8.3	4.6	6.2	5.2	6.5	4.9
संरचना	12.8	10.3	10.8	5.3	6.7	10.2	5.6	5.9
व्यापार, होटल तथा रेस्तरां, परिवहन, तथा संचार	12.0	11.6	10.9	7.5	10.4	12.3	7.0	5.2
वित्त पोषण, बीमा, स्थावर संपदा तथा व्यवसाय सेवाएं	12.6	14.0	12.0	12.0	9.7	10.1	11.7	8.6
समुदाय, सामाजिक तथा वैयक्तिक सेवाएं	7.1	2.8	6.9	12.5	11.7	4.3	6.0	6.8
<b>घटक लागत पर संघट्ट</b>	<b>9.5</b>	<b>9.6</b>	<b>9.3</b>	<b>6.7</b>	<b>8.6</b>	<b>9.3</b>	<b>6.2</b>	<b>5.0</b>

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी: 1स: प्रथम संशोधित अनुमान, 2स: द्वितीय संशोधित अनुमान, अ.अ.: अनंतिम अनुमान।

ही वृद्धि दर दर्ज की, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर इन दो वर्षों के लिए क्रमशः 2.7 प्रतिशत तथा 1.9 प्रतिशत पर और भी निम्नतर रही है, कृषि में वृद्धि भी 2012-13 में कमजोर रही है जिसका कारण विशेषकर दक्षिण-पश्चिम मानसून के आरम्भिक चरणों (जून तथा जुलाई माह) में सामान्य से कम वर्षापात का होना है।

1.4 पांच वर्षों के लिए निरंतर द्विअंकीय वृद्धि हासिल करने तथा छठे वर्ष (2005-06 तथा 2010-11 के बीच) में द्विअंकीय वृद्धि में मामूली सी कम वृद्धि हासिल करने के पश्चात् सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर भी गिर कर 2011-12 में 8.2 प्रतिशत तथा 2012-13 में 6.6 प्रतिशत रह गई। वर्ष 2011-12 में सेवा क्षेत्र में विशेष रूप से अवमंदन दर्शाने वाले क्षेत्र थे व्यापार, होटल तथा रेस्तरां, परिवहन तथा संचार, तथा इसकी वृद्धि में 2012-13 में आगे और गिरावट आई। इस क्षेत्र के क्रियाकलाप अभिप्राप्त मांग के स्वरूप के होने के कारण उद्योग तथा कृषि क्षेत्रों में आर्थिक क्रियाकलापों के अवमंदन के साथ अपेक्षाकृत धीमी दर पर अभिवृद्धि हासिल करने की ओर प्रवृत्त हैं।

1.5 वैश्विक वित्तीय संकट से सशक्त रूप से उभरने के बावजूद अर्थव्यवस्था में इतनी तीव्रता से मंदन क्यों आया है? इसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। प्रथमतः संकट के पश्चात् मौद्रिक तथा राजकोषीय प्रेरण द्वारा मांग को दिया गया बढ़ावा बहुत अधिक था। अंतिम उपभोग में वर्ष 2009-10 तथा 2011-12 के बीच 8 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की औसत दर पर वृद्धि हुई। इसका परिणाम था प्रबल मुद्रास्फीति तथा शक्तिशाली मौद्रिक अनुक्रिया जिसने खपत मांग को भी धीमा कर दिया। दूसरे, वर्ष 2011-12 से कारपोरेट तथा अवसंरचना निवेश में मंदन आना आरम्भ हो गया जिसका कारण निवेश अवरोधों के साथ-साथ अपेक्षाकृत कठोर मौद्रिक नीति का होना था। दुर्भाग्यवश, जब अर्थव्यवस्था में मंदन आया तो इसे दो अतिरिक्त आघात

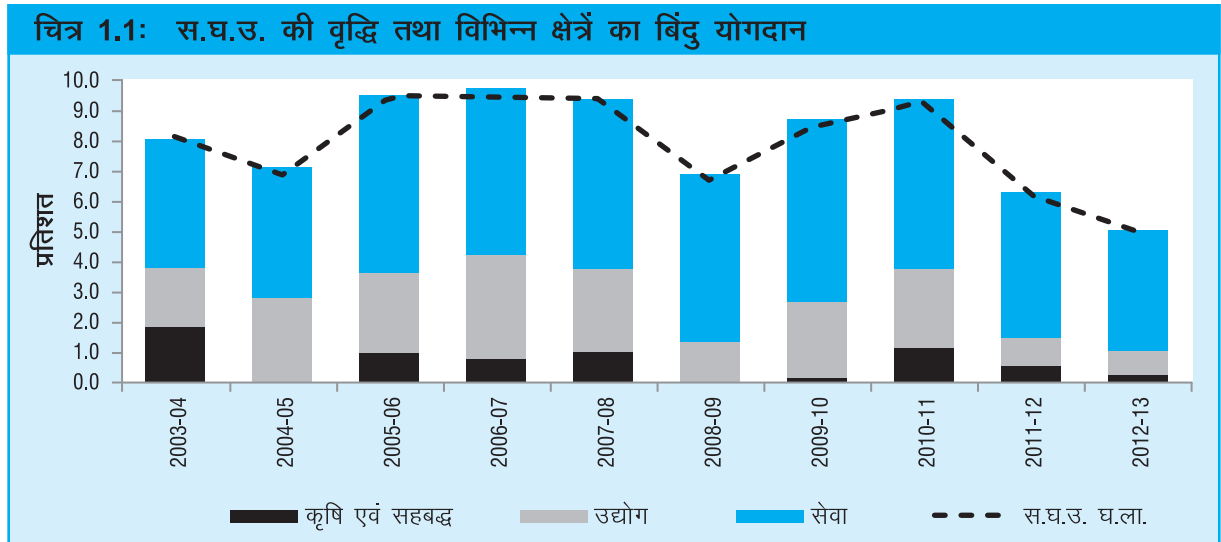
पहुंचे: यूरो क्षेत्र में संकट तथा संयुक्त राज्य अमरीका में राजकोषीय नीति संबंधी अनिश्चितताओं, तथा कम से कम आरम्भिक चरण में एक कमजोर मानसून, से प्रतिकूलतः प्रभावित होती एक अवमंदनकारी वैश्विक अर्थव्यवस्था।

1.6 जैसे जैसे वृद्धि में धीमापन आया तथा सरकारी राजस्व व्यय के समनुरूप नहीं रहे, राजकोषीय घाटे में लक्ष्य का उल्लंघन होने का खतरा बढ़ गया। सरकारी बचतों के कम होने, तथा निजी बचतों के भी संकुचित होने से, सीएडी-जो ऐसा निवेश है जिसका वित्तपोषण घरेलू बचतों से नहीं किया जा सकता तथा जिसका वित्तपोषण विदेशों द्वारा ही किया जाना है, भी व्यापक हो गया। इस अध्याय के शेष भाग में, बृहद् अर्थव्यवस्था की सांख्यिकीय कमियों का विश्लेषण किया गया है जिसके पश्चात् बृहद् आर्थिक सुस्थिरीकरण के लिए तथा संवृद्धि बहाल करने के लिए सरकार की नीति का तर्काधार बनाया गया है। अध्याय की समाप्ति बृहद् आर्थिक परिदृश्य तथा परिदृश्य के लिए संभावनी जोखिमों पर चर्चा के साथ की गई है।

1.7 आर्थिक सर्वेक्षण में मात्र अर्थव्यवस्था का विश्लेषण नहीं किया जाता; यह अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटनाक्रमों का एक ब्यौरेवार अभिलेख भी है। अतः बृहद् आर्थिक विश्लेषण के पश्चात् सर्वेक्षण के अन्य अध्यायों का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत किया गया है।

## संवृद्धि के पहलू

1.8 पिछले दशक में संवृद्धि वर्धनात्मक रूप से सेवा क्षेत्रक में हुई जिसका अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि में योगदान 65 प्रतिशत रहा है जबकि उद्योग तथा कृषि क्षेत्रों का योगदान क्रमशः 27 प्रतिशत तथा 8 प्रतिशत रहा है। चित्र 1.1 में वर्ष 2003-07 से 2012-13 तक क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि में योगदान दर्शाया गया है।



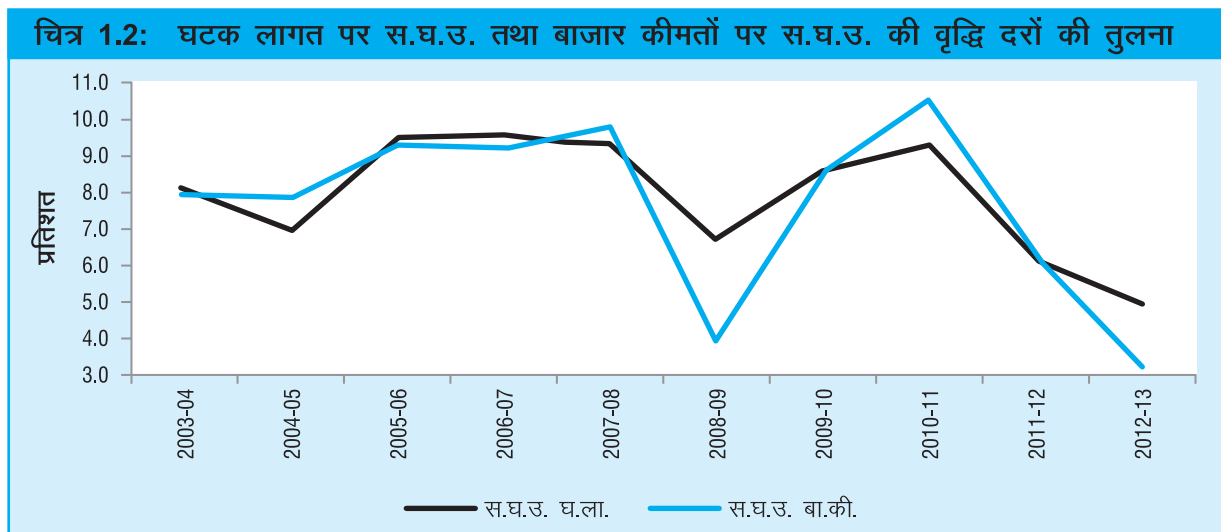
टिप्पणी: वर्ष 2012-13 के लिए आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा अग्रिम अनुमानों के अनुसार हैं।

1.9 चित्र 1.1 से संकेत मिलता है कि 9 प्रतिशत या उससे अधिक की संवृद्धि दर हासिल करने के लिए, अर्थव्यवस्था के सभी तीन मुख्य क्षेत्रों का निष्पादन अच्छा होना चाहिए। कृषिय वृद्धि का हिस्सा समग्र योगदान में कम होने के बावजूद अधिक अवमंदित वृद्धि से वर्षों से सशक्त समग्र वृद्धि के वर्ष सुस्पष्ट परिलक्षित होते हैं। फिर भी दो अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र समग्र वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2005-06 से 2007-08 के साथ-साथ 2009-10 तथा 2010-11 के उच्च संवृद्धि वर्षों में, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र, दोनों की संवृद्धि दर 9 प्रतिशत से अधिक थी। इन वर्षों में उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र का निष्पादन अर्थव्यवस्था के अधिकांश अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक बेहतर रहा। इसकी औसत वृद्धि 2005-06 तथा 2007-08 के वर्षों के बीच 11.6 प्रतिशत रही तथा 2009-10 एवं 2010-11 के बीच यह 10.5 प्रतिशत थी। पूर्वोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि संवृद्धि के सशक्त होने के लिए उद्योग क्षेत्र का तथा विशेष कर विनिर्माण क्षेत्र का योगदान आने वाले वर्षों में बढ़ना

आवश्यक है। यह कृषि क्षेत्र से अधिशेष श्रमिकों को समाहित करने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं (देखें अध्याय 2)।

1.10 हालिया वर्षों में सामान्य पैटर्न यह रहा है कि अत्यधिक उच्चतर वृद्धि के वर्षों में बाजार कीमतों पर स.घ.उ. की वृद्धि घटक लागत पर स.घ.उ. में बढ़ जाती है तथा धीमी वृद्धि के वर्षों में यथार्थता इसकी प्रतिवर्ती है (चित्र 1.2)

1.11 घटक लागत पर स.घ.उ. अप्रत्यक्ष करों को घटाकर तथा आर्थिक सहायता को जोड़कर बाजार कीमतों पर स.घ.उ. है। घटक लागतों पर वृद्धि तथा बाजार कीमतों पर वृद्धि में अंतर का कारण अंशतः इस तथ्य में सन्निहित है कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि की प्रवृत्ति मंदी के दौर में कम होने की होती है। जबकि आर्थिक सहायता पर व्यय अक्सर बढ़ जाता है। इसमें निवल अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि कम हो जाती है, मंदी की स्थिति में दोनों मदों के बीच यही अंतर है। उदाहरणार्थ, स.घ.उ. के प्रति निवल अप्रत्यक्ष करों का अनुपात 2003-04 तथा 2007-08 में 8.1 प्रतिशत के औसत



सारणी 1.2 : सतत् बाजार कीमतों पर स.घ.उ. में वृद्धि ( प्रतिशत )								
	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 <sup>2स</sup>	2011-12 <sup>1स</sup>	2012-13 <sup>अ.अ.</sup>
<b>1. कुल अंतिम उपभोग व्यय</b>	<b>8.7</b>	<b>7.7</b>	<b>9.4</b>	<b>7.7</b>	<b>8.4</b>	<b>8.1</b>	<b>8.1</b>	<b>4.1</b>
1.1 निजी अंतिम उपभोग व्यय	8.6	8.5	9.4	7.2	7.4	8.6	8.0	4.1
1.2 सरकारी अंतिम उपभोग व्यय	8.9	3.8	9.6	10.4	13.9	5.9	8.6	4.1
<b>2. सकल पूंजी निर्माण</b>	<b>16.2</b>	<b>13.4</b>	<b>18.1</b>	<b>-5.2</b>	<b>17.3</b>	<b>15.2</b>	<b>0.5</b>	<b>3.9</b>
2.1 सकल नियत पूंजी निर्माण	16.2	13.8	16.2	3.5	7.7	14.0	4.4	2.5
2.2 स्टॉक में परिवर्तन	26.7	31.6	31.3	-51.4	67.7	29.7	-30.6	47.6
2.3 मूल्यवान वस्तुएं	-1.6	13.7	2.9	26.9	57.6	32.4	6.6	-18.1
<b>3. निर्यात</b>	<b>26.1</b>	<b>20.4</b>	<b>5.9</b>	<b>14.6</b>	<b>-4.7</b>	<b>19.7</b>	<b>15.3</b>	<b>5.1</b>
<b>4. घटाए आयात</b>	<b>32.6</b>	<b>21.5</b>	<b>10.2</b>	<b>22.7</b>	<b>-2.1</b>	<b>15.8</b>	<b>21.5</b>	<b>5.7</b>
2004-05 बाजार कीमतों पर स.घ.उ. में वृद्धि	9.3	9.3	9.8	3.9	8.5	10.5	6.3	3.3

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

टिप्पणियां : 1स: प्रथम संशोधित अनुमान, 2स: द्वितीय संशोधित अनुमान, अ.अ.: अग्रिम अनुमान, भूलचूक के लिए समायोजन के कारण संभवतया जोड़ मेल न खाएं।

से गिरकर 2008-09 तथा 2009-10 में 5.7 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहुंच गया। यही कारण था कि घटक लागत पर स.घ.उ. की वृद्धि 2008-09 में बाजार कीमतों पर स.घ.उ. की वृद्धि से उच्चतर थी।

1.12 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुरूप, बाजार कीमतों (2004-05 की कीमतों पर) पर स.घ.उ. के संदर्भ में वृद्धि दर के 2011-12 में 6.3 प्रतिशत की तुलना में 2012-13 में 3.3 प्रतिशत होने की आशा है (सारणी 1.2)। निवेश दर में अपचयन तथा आयातों की वृद्धि की तुलना में निर्यातों की

अपेक्षाकृत निम्न वृद्धि के कारण संवृद्धि दर में महत्वपूर्ण गिरावट आई। उपभोग व्यय की वृद्धि दर तथा विशेष रूप से निजी अंतिम उपभोग व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 को छोड़कर सामान्यतः निवेश से अधिक स्थिर रही है।

### स.घ.उ. की वृद्धि के त्रैमासिक अनुमान

1.13 सारणी 1.3 में वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 की प्रथम तिहाहियों के लिए अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में घटक लागत पर (सतत् 2004-05 कीमतों पर) स.घ.उ. की तिमाही वृद्धि

सारणी 1.3 : सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के त्रैमासिक अनुमान ( वर्षानुवर्ष प्रतिशत )										
क्षेत्र	2010-11				2011-12				2012-13	
	ति. 1	ति. 2	ति. 3	ति. 4	ति. 1	ति. 2	ति. 3	ति. 4	ति. 1	ति. 2
<b>1. कृषि, वानिकी और मात्स्यिकी उद्योग</b>	<b>3.1</b>	<b>4.9</b>	<b>11.0</b>	<b>7.5</b>	<b>3.7</b>	<b>3.1</b>	<b>2.8</b>	<b>1.7</b>	<b>2.9</b>	<b>1.2</b>
2. खनन और उत्खनन	8.3	5.7	7.6	7.0	5.6	3.7	2.5	1.9	3.6	2.8
3. विनिर्माण	6.9	7.3	6.1	0.6	-0.2	-5.4	-2.8	4.3	0.1	1.9
4. बिजली, गैस और जलापूर्ति	9.1	6.1	7.8	7.3	7.3	2.9	0.6	-0.3	0.2	0.8
5. संरचना सेवाएं	2.9	0.3	3.8	5.1	8.0	9.8	9.0	4.9	6.3	3.4
6. व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	8.4	6.0	8.7	8.9	3.5	6.3	6.6	4.8	10.9	6.7
7. वित्तपोषण, बीमा, स्थावर संपदा और कारोबारी सेवाएं	<b>10.0</b>	<b>9.1</b>	<b>7.7</b>	<b>10.6</b>	<b>10.2</b>	<b>8.8</b>	<b>8.9</b>	<b>7.9</b>	<b>6.9</b>	<b>7.2</b>
8. सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	12.6	10.6	9.7	11.6	13.8	9.5	10.0	7.0	4.0	5.5
9. घटक लागत पर कुल स.घ.उ. (जोड़ 1-8)	10.0	10.4	11.2	10.0	9.4	9.9	9.1	10.0	10.8	9.4
	4.4	4.5	-0.8	9.5	3.2	6.1	6.4	7.1	7.9	7.5
	<b>8.5</b>	<b>7.6</b>	<b>8.2</b>	<b>9.2</b>	<b>8.0</b>	<b>6.7</b>	<b>6.1</b>	<b>5.3</b>	<b>5.5</b>	<b>5.3</b>

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

## 6 आर्थिक समीक्षा 2012-13

दरें दी गई हैं। वर्ष 2011-12 में मंदी व्यापकाधारित थी तथा 2012-13 में यह और भी अधिक व्यापकाधारित हो गई है।

1.14 भारत में तिमाही स.घ.उ. वृद्धि दर में 2010-11 की चौथी तिमाही तथा 2011-12 की चौथी तिमाही के बीच प्रत्येक क्रमिक तिमाही में गिरावट आई। चालू वर्ष के प्रथमार्ध में वृद्धि 5.4 प्रतिशत परिकलित होती है जबकि वर्ष 2012-13 के लिए वृद्धि के सीएसओ के अग्रिम अनुमान के अनुसार यह 5.0 प्रतिशत है। और अब हम सकल मांग के कुछ प्रमुख तत्वों का विश्लेषण यह देखने के लिए करें कि अर्थव्यवस्था में मंदन क्यों आया है।

### निजी अंतिम उपभोग व्यय

1.15 निजी अंतिम उपभोग व्यय बाजार कीमतों पर स.घ.उ. का लगभग 3/5वां हिस्सा बैठता है। लोगों की व्यय योग्य आय में वृद्धि से कुल खपत में खाद्य अंश कमी की ओर प्रवृत्त है (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएमएसओ) का खपत व्यय संबंधी सर्वेक्षण कुल खपत में खाद्य अंश में अद्योमुखी रुझान का सुस्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध कराता है)। अतः प्रत्याशित रूप से खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों तथा तम्बाकू समूह पर व्यय की संवृद्धि दर कुल निजी अंतिम उपभोग व्यय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत कम है जिसके परिणामस्वरूप इसका हिस्सा 2004-05 में 40 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2011-12 में 31.2 प्रतिशत रह गया है (सारणी 1.4)

1.16 विगत वर्ष में, निजी अंतिम उपभोग व्यय में महत्वपूर्ण मंदी आई है और यह 2011-12 में 8 प्रतिशत से कम होकर 2012-13 में 4.1 प्रतिशत रह गया है (सारणी 1.2)। काफी अधिक संख्या में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि दर में महत्वपूर्ण गिरावट आई। उदाहरणार्थ निजी वाहनों की वृद्धि दर अप्रैल-नवम्बर 2011 में 23.2 प्रतिशत से कम होकर अप्रैल-नवम्बर, 2012 में -5.6 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार, प्रपुंज्जन खपत के लिए उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि दर अप्रैल-नवम्बर 2011 में 12.2 प्रतिशत से घटकर अप्रैल-नवम्बर 2012 में 3.3 प्रतिशत रह गई।

1.17 खपत में सामान्य मंदी का आंशिक कारण यह हो सकता है कि उच्चतर मुद्रास्फीति परिवारों की वास्तविक निपटान योग्य आय को घटाने की ओर प्रवृत्त होती है। टिकाऊ वस्तुओं की खपत में वृद्धि (इस अनुमान के साथ कि इन मंदों के लिए उपभोग वृद्धि उत्पादन में वृद्धि से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं होगी) हाल ही में और मंद हो गई होगी क्योंकि उच्च ब्याज दरों तथा परिणामी उच्च मासिक किस्तों ने क्रय को नियंत्रित किया है। साथ ही, मौसमी रूप से समायोजित औद्योगिक उत्पादन का उपभोक्त गैर टिकाऊ वस्तु सूचकांक (आईआईपी), जो पारम्परिक रूप से टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन की तुलना में एक सहज श्रृंखलन है, में अगस्त 2012 से तेजी आ रही है।

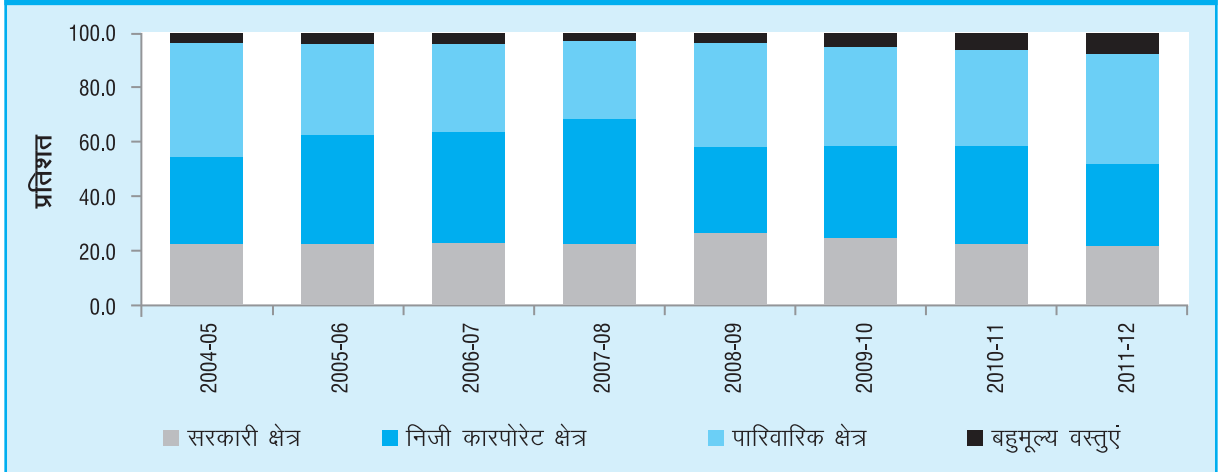
सारणी 1.4 : निजी अंतिम उपभोग व्यय : 2004-05 कीमतों पर वार्षिक वृद्धि तथा अंश

	2004-05	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 <sup>1स</sup>	2011-12 <sup>2स</sup>
	<b>वार्षिक वृद्धि ( प्रतिशत )</b>						
खाद्य, पेय पदार्थ और तम्बाकू		3.4	6.4	3.3	0.4	5.9	5.8
कपड़े और जूते		23.3	5.0	5.0	14.9	20.2	-3.9
सकल किराया, ईंधन और बिजली		3.8	4.7	3.6	6.0	4.2	6.2
फर्नीचर, फर्निशिंग आदि		17.1	16.1	12.2	9.0	16.6	6.2
चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं		8.7	4.5	6.9	8.9	7.6	6.2
परिवहन और संचार		9.1	7.9	7.7	12.1	10.0	9.8
मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक सेवाएं		8.4	9.8	6.8	4.0	11.8	8.1
प्रकीर्ण वस्तुएं और सेवाएं		21.1	28.6	20.2	15.7	7.9	19.1
<b>कुल निजी उपभोग व्यय</b>		<b>8.7</b>	<b>9.2</b>	<b>7.1</b>	<b>7.5</b>	<b>8.7</b>	<b>7.9</b>
	<b>योग में हिस्सा ( प्रतिशत )</b>						
खाद्य, पेय पदार्थ और तम्बाकू	40.0	37.3	36.3	35.0	32.7	31.8	31.2
कपड़े और जूते	6.6	8.3	8.0	7.8	8.4	9.3	8.2
सकल किराया, ईंधन और बिजली	13.8	12.6	12.1	11.7	11.5	11.1	10.9
फर्नीचर, फर्निशिंग आदि	3.4	3.9	4.1	4.3	4.4	4.7	4.6
चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएं	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.7
परिवहन और संचार	19.3	18.9	18.7	18.8	19.6	19.8	20.2
मनोरंजन, शिक्षा और सांस्कृतिक सेवाएं	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0
प्रकीर्ण वस्तुएं और सेवाएं	8.9	11.0	13.0	14.6	15.7	15.6	17.2
<b>कुल निजी उपभोग व्यय</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

टिप्पणियां : 1स: प्रथम संशोधित अनुमान, 2स: द्वितीय संशोधित अनुमान।

**चित्र 1.3: विभिन्न प्रकार की संस्थाओं द्वारा निवेश**



### निवेश

1.18 वर्ष 2003-04 से अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का निवेश दर के साथ सशक्त सहसंबंध रहा है। वर्ष 2003-04 तथा 2011-12 के बीच निवेश दर औसतन 34.5 प्रतिशत थी जो पहले की दर से काफी उच्च है। जैसाकि सारणी 1.1 तथा 1.2 से देखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था में वास्तविक वृद्धि दर 2005-06 से 2007-08 के दौरान औसतन 9.5 प्रतिशत प्रति वर्ष रही, यही वे वर्ष थे जब वास्तविक अर्थ में निवेश की वृद्धि दर औसतन लगभग 16 प्रतिशत रही। इसी प्रकार, अर्थव्यवस्था की औसत वृद्धि दर वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में लगभग 9 प्रतिशत प्रति वर्ष थी जिसमें निवेश की वृद्धि दर इन दो वर्षों में औसतन 16.2 प्रतिशत रही। स.घ.उ. की वृद्धि दर उन वर्षों में निम्नतर थी जब निवेश की वृद्धि दर निम्न थी, यह स्थिति वर्ष 2008-09 तथा 2011-12 में थी।

1.19 जैसा कि सारणी 1.5 से देखा जा सकता है, निजी क्षेत्र देश में निवेश का प्रमुख स्रोत है। निजी क्षेत्र के अंतर्गत, निवेशकों की दो श्रेणियां हैं अर्थात् निजी कारपोरेट क्षेत्र तथा पारिवारिक क्षेत्र। चित्र 1.3 में कुल निवेश में इन क्षेत्रों का हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र तथा बहुमूल्य वस्तुओं के निवेश सहित दर्शाया गया है।

1.20 वर्ष 2004-05 से जो वह वर्ष था जब अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश दर पहले 30 प्रतिशत को पार कर गई थी, कुल निवेश (बहुमूल्य वस्तुओं को छोड़कर) में सरकारी निवेश का हिस्सा सभी वर्षों में लगभग 24 प्रतिशत पर सुस्थिर रहा है सिवाए वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के जब यह क्रमशः 27.6 प्रतिशत तथा 26.5 प्रतिशत था। इन वर्षों में वृद्धि का कारण वैश्विक मंदी के पश्चात् सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 में अर्थव्यवस्था में अवमंदन को दूर करने के उद्देश्य से प्रदत्त राजकोषीय अभिप्रेरण को माना जा सकता है।

**सारणी 1.5 : स.घ.उ. की तुलना में निवेश का अनुपात ( चालू बाजार कीमतों पर प्रतिशत )**

	2004-05	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 <sup>2स</sup>	2011-12 <sup>1स</sup>
<b>1. सकल पूंजी निर्माण</b>	<b>32.8</b>	<b>35.7</b>	<b>38.1</b>	<b>34.3</b>	<b>36.5</b>	<b>36.8</b>	<b>35.0</b>
सरकारी क्षेत्र	7.4	8.3	8.9	9.4	9.2	8.4	7.9
निजी क्षेत्र	23.8	26.4	28.1	24.8	25.4	26.5	24.9
कारपोरेट क्षेत्र	10.3	14.5	17.3	11.3	12.1	13.4	10.6
पारिवारिक क्षेत्र	13.4	11.9	10.8	13.5	13.2	13.1	14.3
<b>2. सकल नियत पूंजी निर्माण</b>	<b>28.7</b>	<b>31.3</b>	<b>32.9</b>	<b>32.3</b>	<b>31.7</b>	<b>31.7</b>	<b>30.6</b>
स्टॉक	2.5	3.4	4.0	1.9	2.8	3.1	2.1
मूल्यवान वस्तुएं	1.3	1.2	1.1	1.3	1.8	2.1	2.7
<b>3. सकल घरेलू बचतें</b>	<b>32.4</b>	<b>34.6</b>	<b>36.8</b>	<b>32.0</b>	<b>33.7</b>	<b>34.0</b>	<b>30.8</b>
<b>4. बचत निवेश अंतर ( 3-1 )</b>	<b>-0.4</b>	<b>-1.1</b>	<b>-1.3</b>	<b>-2.3</b>	<b>-2.8</b>	<b>-2.8</b>	<b>-4.2</b>

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय टिप्पणी : 1स: प्रथम संशोधित अनुमान, 2स: द्वितीय संशोधित अनुमान। भूल-चूक और त्रुटियों के लिए किए गए समायोजन के कारण जोड़ में अंतर हो सकता है।

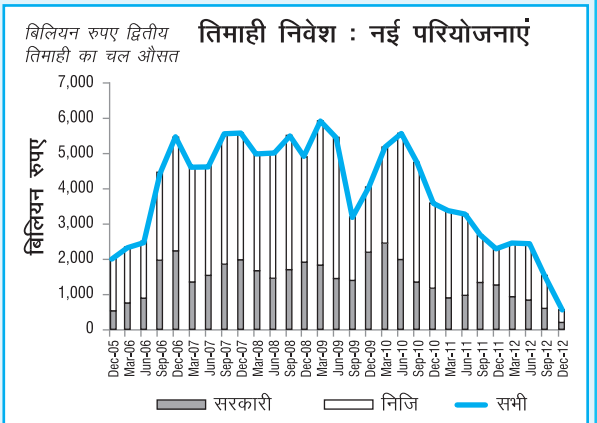
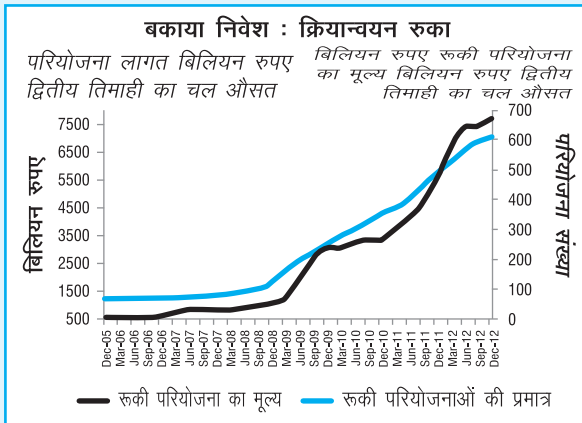
1.21 जनवरी 2013 में सीएसओ द्वारा जारी प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार, वर्तमान बाजार कीमतों (निवेश दर) पर स.घ.उ. के अनुपात के रूप में सकल घरेलू पूंजी निर्माण के 2010-11 में 36.8 प्रतिशत की तुलना में 2011-12 में 35.0 प्रतिशत होने का अनुमान है, सरकारी तथा निजी निवेश, दोनों में स.घ.उ. के हिस्से के रूप में गिरावट आई। निजी निवेश के अंतर्गत, निजी कारपोरेट क्षेत्र द्वारा निवेश ने अपेक्षाकृत तीव्र गिरावट दर्ज की।

1.22 निजी निवेश में अपचयन अनेक कारणों के कारण हुआ, प्रथम कारण नीतिगत दरों में की गई वृद्धि है (ऐसा मुद्रास्फीति तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं का सामना करने के लिए किया गया था)। मार्च 2010 तथा अक्टूबर 2011 के बीच, भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपो दर में 375 आधार अंकों की वृद्धि की जिसमें मांग को कम करने के प्रयास में उधारों की लागत बढ़ी। निम्नतर निजी निवेश का एक अन्य कारण विश्व के शेष भाग, विशेषतया प्रगत देशों से

**बॉक्स 1.1 : निवेश के हालिया रुझान: रूक गई परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि तथा शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं की संख्या में कमी**

निवेशों में दो रुझान प्रबल हैं- रूक गई परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि तथा शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं की संख्या में कमी, इनका अध्ययन करने के लिए हम सीएमआईई के केपेक्स डाटा से आंकड़ों का प्रयोग करते हैं जो परियोजना विशिष्ट स्तर पर निवेशों का अनमार्गण करता है।

**रूक गई परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि:** ऐसी परियोजनाओं की संख्या बढ़ी है जहां क्रियान्वयन को आस्थगित कर दिया गया है। मूल्य तथा प्रमात्रा, दोनों के अर्थ में, रूक गई परियोजनाओं की संख्या वर्ष 2009 से बढ़ रही है। दिसम्बर 2012 कि स्थिति के अनुसार, छः क्षेत्र सभी रूक गई परियोजनाओं के लगभग 80 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी थे बिजली, सड़क, दूरसंचार सेवाएं, इस्पात, स्थावर सम्पदा तथा खनन।



स्रोत: सीएमआईई केपेक्स

**शुरू की जाने वाली नई परियोजनाओं की संख्या में कमी**

सभी क्षेत्रों में नवीन निवेश परियोजनाएं आरंभ नहीं हो रही हैं जिसका अंशतः कारण रूक गई परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि का होना है जिससे फर्मों का नई परियोजनाएं शुरू करने के सामर्थ्य कम हो जाता है। निजी क्षेत्रक तथा सरकारी, दोनों प्रकार की परियोजनाओं में कमी आ रही है। सरकारी परियोजनाएं मार्च 2010 में चरम स्तर पर थी तथा निजी क्षेत्र परियोजनाओं ने चरम स्तर दो तिमाही के अंतराल पर बाद में हासिल किया। तभी से निजी क्षेत्रक निवेश स्तर सरकारी निवेशों से लगभग छः माह पीछे है।

**धीमेपन के कारण:** निवेशों के रूप जाने तथा नई परियोजनाएं शुरू न किए जाने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी माने जाते हैं। एक सीएमआईई अध्ययन दर्शाता है कि वर्ष 2011-12 में 20 परियोजनाएं छोड़ दी गई परियोजनाओं की कुल लागत के लगभग 70 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी थी। इन 20 व्यष्टि, परियोजनाओं का विश्लेषण भूमि अधिग्रहण में कठिनाई कोयला संवहन तथा खनन प्रतिबंधों को प्रमुख कारणों के रूप में सुझता है। अन्य रूकी हुई परियोजनाओं के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि नीतिगत मुद्दों, जैसे दूर संचार स्पेक्ट्रम आवंटनों में नीतिगत मुद्दों ने भी इसमें एक भूमिका निभाई है। अनेक क्षेत्रक जैसे उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुएं, जो उपर वर्णित किस्म की अनुमतियों के कम अध्यधीन है तथा मांग दशाओं और स.घ.उ. की वृद्धि द्वारा अधिक प्रेरित हैं, भी नए निवेशों में धीमेपन को परिलक्षित कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, खाद्य तथा वृद्धि आधारित उत्पादों के विनिर्माण के नए निवेशों में मंदन आया है। वृद्धि का अभाव तथा निवेश में मंदन एक दूसरे को प्रतिकूलतः प्रभावित कर रहा है जिसके लिए दोनों ओर के कारण उत्तरदायी है। उच्च ब्याज दरों ने भी इन निराशाजनक निवेश माहौल में योगदान दिया है। तथापि अप्रैल तथा दिसम्बर 2012 के बीच रिपो में स्थिरता, को देखते हुए, नवीनतम तिमाही आंकड़े सुझाते हैं कि कम्पनियों की ब्याज लागतों में मामूली सा संतुलन आया है।

**भावी योजना :** सरकार ने निवेशों की शुरूआत करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीआई) का गठन 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को त्वरित करने के लिए किया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा समाशोधित भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (एलएआरआर) विधेयक से अधिक स्पष्टता आएगी अनिश्चितता कम होगी तथा इस प्रकार निवेशों को सहायता मिलेगी। नकदी समृद्ध सरकारी क्षेत्रक इकाइयों द्वारा निवेशों में निजी क्षेत्र की संभाव्यता को प्राप्त करने की संभाव्यता है। दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारे पर प्रगति में देश के निवेश माहौल को बढ़ावा देने की संभाव्यता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कटौती तथा बेहतर होते व्यवसाय मनोभाव भी निवेशों के पुनरुत्थान में सहायक होंगे।

“परियोजनाओं में तीव्र वृद्धि कम हुई,” सीएमआईई, मई 2012



भारतीय निर्यातों के लिए निम्नतर मांग का होना हो सकता है। निम्नतर कारपोरेट निवेश का एक तीसरा संभव कारण नीतिगत बाधाएं हैं (जैसे पर्यावरणीय अनुमतियां हासिल करना, ईंधन संबंधन या भू-अधिग्रहण का संचालन, देखें बाक्स 1.1) जो अनेक बड़ी परियोजनाओं के रूक जाने में परिणामी हुआ जिसके बदले में नए निवेश हतोत्साहित हुए। इसके पश्चात् निवेश की विभिन्न संघटकों में हालिया रूझानों पर चर्चा समग्र निवेश दर में गिरावट को समझने के लिए की गई है।

1.23 वर्ष 2004-05 तथा 2011-12 के बीच पारिवारिक क्षेत्र तथा निजी कारपोरेट क्षेत्र का कुल निजी निवेश में हिस्सा औसतन कमाधिक समान रहा है। तथापि, हर वर्ष भारी उतार चढ़ाव होते हैं जिनमें निजी कारपोरेट क्षेत्र का हिस्सा 2005-06 से 2007-08 के उच्च वृद्धि वर्षों में महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर था तथा निम्नतर वृद्धि के वर्षों में, विशेषकर 2008-09 तथा 2011-12 में काफी निम्नतर था। वर्तमान कीमतों पर निजी कारपोरेट क्षेत्र द्वारा निवेश 2010-11 की तुलना में 2011-12 में लगभग 90,000 करोड़ रुपए निम्नतर था। परिणामतः कुल निवेश में निजी कारपोरेट निवेश का हिस्सा 2010-11 में 36.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2011-12 में 29.8 प्रतिशत हो गया। तुलनात्मक रूप से, गिरावट के परिणाम 2008-09 में कहीं अधिक था जब निजी कारपोरेट निवेश में 2007-08 की तुलना में लगभग 2,25,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई।

1.24 आंकड़ों का आगे और विश्लेषण करने से पता चलता है कि वर्ष 2011-12 में निजी कारपोरेट क्षेत्र द्वारा निवेश में अपचयन स्टॉकों की कमी के कारण था। वर्ष 2008-09 के विपरीत, जब निजी कारपोरेट क्षेत्र में सकल नियत निवेश में वर्ष 2007-08 की तुलना में लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई, निजी कारपोरेट क्षेत्र द्वारा सकल नियत पूंजी निर्माण ने 2010-11 की तुलना में 2011-12 में सीमांतिक वृद्धि दर्ज की, वस्तुतः, वास्तविक अर्थों में तथा साथ ही कुल निवेश की प्रतिशतता के अर्थ में, निजी कारपोरेट क्षेत्र का सकल नियत निवेश भी 2010-11 की तुलना में 2011-12 में कम हो गया। यह देखते हुए कि उत्पादक निवेश अवमंदित होने पर भी वर्ष 2009-12 में खपत के सशक्त वृद्धि हुई, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि अर्थव्यवस्था में आपूर्ति की वर्धनात्मक कमी हुई है।

1.25 बहुमूल्य वस्तुओं के रूप में निवेश 2010-14 की तुलना में 2011-12 में लगभग 80,000 करोड़ रुपए बढ़ा। बहुमूल्य वस्तुओं में कला कृतियां, बहुमूल्य धातुएं तथा ऐसी धातुओं तथा पत्थरों में बने आभूषण शामिल हैं। वर्तमान कीमतों पर, मूल्यवान वस्तुओं के रूप में निवेश में 2007-08 तथा 2011-12 में लगभग 4.5 गुणा वृद्धि दर्ज हुई तथा कुल निवेश में उनका हिस्सा 2007-08 में 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 7.6 प्रतिशत हो गया। इस हिस्से में वृद्धि का आंशिक कारण स्वर्ण तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि का होना है। तथापि, सतत्

कीमतों पर भी बहुमूल्य वस्तुओं का हिस्सा 2007-08 में 2.9 प्रतिशत से बढ़ कर 2011-12 में 6.2 प्रतिशत होगा जो स्वर्ण सहित बहुमूल्य वस्तुओं की अपेक्षाकृत अधिक खरीद को इंगित करता है। वर्ष 2012-13 के लिए सी एस ओ के अग्रिम अनुमान सुझाते हैं कि बहुमूल्य वस्तुओं की खरीद में वास्तविक अर्थ में गिरावट आई है।

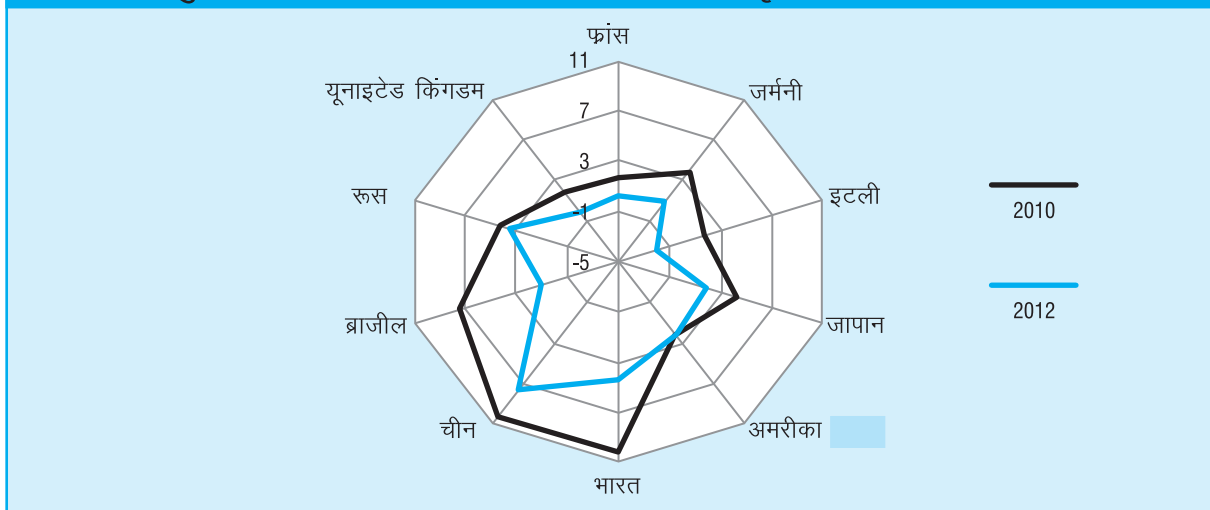
1.26 संक्षेप में, समग्र निवेश में कुछ कुछ धीमापन आया है किन्तु इसे अनुत्पादक निवेश जैसे मूल्यवान वस्तुओं में निवेश द्वारा कायम रखा जा रहा है। विशेष रूप से चिंताजनक कारपोरेट निवेश में तीव्र मंदन है जो भावी आपूर्ति (मुद्रास्फीति को कम करने के लिए आवश्यक) तथा भावी वृद्धि संभाव्यता का स्रोत है। निवेश अवरोधों को दूर करने के लिए नीतियों के साथ-साथ निवेश तथा इसके वित्त पोषण को प्रोत्साहन देने के लिए संरचनात्मक सुधार आवश्यक है तथा साथ ही मुद्रास्फीति के प्रशमन के साथ-साथ समायोजक मौद्रिक नीति भी आवश्यक है।

## निवल निर्यात

1.27 निवल निर्यातों में वृद्धि मांग का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती हैं। दुर्भाग्यवश भारत के लिए निवल निर्यात वृद्धि वैश्विक कमजोरी के कारण निम्न रही है। जनवरी 2013 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी वर्ल्ड इकानामिक आऊटलुक अपडेट में वैश्विक उत्पादन की वृद्धि दर 2011 में 3.9 प्रतिशत तथा 2012 के 3.2 प्रतिशत जो 2010 में 5.1 प्रतिशत से कम है। प्रगत अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह वृद्धि दर 2010, 2011 तथा 2012 के लिए क्रमशः 3 प्रतिशत, 1.6 प्रतिशत तथा 1.3 प्रतिशत पर काफी निम्नतर थी। तीव्र विकासशील उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर में भी इस अवधि में गिरावट आई। चित्र 1.4 में 2010 तथा 2012 के लिए चुनिंदा प्रगत तथा उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं के लिए वृद्धि दरें दी गई हैं (डब्ल्यूईओ से उपलब्ध जानकारी पर आधारित)

1.28 कारोबारी भागीदार देशों में कमजोर वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय निर्यातों में भी गिरावट आई (अध्याय 7 में बाक्स 7.1 देखें)। वित्त वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध (अप्रैल-सितम्बर 2012) में निर्यातों में तीव्र गिरावट आई (देखें सारणी 1.6)। प्रतिशतांक बिंदु संदर्भ में आयातों में उतनी अधिक कमी नहीं आई। उन लचीले तेल आयात आयातों की सापेक्ष स्थिरता का प्रमुख कारण थे, किन्तु स्वर्ण आयातों में, जिनमें हालिया वर्षों में स्वर्ण धारिताओं पर उच्चतर परिकल्पित प्रतिफलों के कारण उछाल आया है, आयातों में महत्वपूर्ण योगदान दिया यद्यपि विगत वर्षों में उनके मूल्य में कमी आई है (बाक्स 1.2)। इस का निवल परिणाम व्यापार घाटे का 2011-12 के प्रथमार्ध में स.घ.उ. के 9.9 प्रतिशत की तुलना

**चित्र 1.4: चुनिंदा अर्थव्यवस्थाओं के वास्तविक स.घ.उ. की वृद्धि दर**



में बढ़कर 2012-13 के प्रथमार्ध में स.घ.उ. का 10.8 प्रतिशत हो जाना है।

1.29 निवल अदृश्य शेष (जिसमें निवल सेवा निर्यात तथा प्रेषण प्रमुख हैं) सामान्यतः व्यापार घाटे को संतुलित कर देते हैं। किन्तु इनमें भी 2011-12 के प्रथमार्ध के सापेक्षतया 2012-13 के प्रथमार्ध में डालर अर्थ में गिरावट आई। विदेशियों को निवेश आय के वर्धित बहिःप्रवाह ने भी निवल अदृश्य प्राप्तियों को कम करने में भूमिका निभाई है। व्यापार घाटे के बढ़ने तथा निवल अदृश्य अधिशेष के कम होने के परिणामस्वरूप, चालू खाता घाटा 2011-12 के प्रथमार्ध में स.घ.उ. के 4.0 प्रतिशत की तुलना में बदतर होकर 2012-13 के प्रथमार्ध के दौरान 4.6 हो गया।

1.30 इस प्रकार वर्ष 2012-13 में निवेश, खपत तथा निवल निर्यात, सभी के मंद होने में केवल सरकारी व्यय में वृद्धि ही

आर्थिक वृद्धि को बनाए रख सकती थी। किन्तु सरकारी घाटा पहले ही भारत को पश्च वैश्विक वित्तीय संकट के गड्डे से उभारने की विगत विस्तारकारी नीति के परिणामस्वरूप अत्यधिक बढ़ चुका था। इसमें आगे और वृद्धि हुई जब धीमी वृद्धि ने राजस्व को हासिल किया।

### लोक वित्त

1.31 वैश्विक वित्तीय संकट तथा उसके पश्चात सकल मांग में होने वाले मंदी के पश्चात वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में राजकोषीय प्रेरण का अंतःक्षेपण किया गया तथा केन्द्र का राजकोषीय घाटा बढ़कर स.घ.उ. का क्रमशः 6.0 प्रतिशत तथा 6.5 प्रतिशत हो गया। राजकोषीय प्रेरण को अंशतः वापस ले लिए जाने से वर्ष 2010-11 में राजकोषीय समेकन बहाल हुआ। स.घ.उ. में वृद्धि के 2010-11 में तीव्रता से सुधारने के साथ केन्द्र का राजकोषीय घाटा घटकर स.घ.उ. का 4.8 प्रतिशत रह गया। यह अधिकांशतः सांकेतिक स.घ.उ. में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के कारण था।

1.32 वृद्धि के लड़खड़ा जाने से 2011-12 में इस संवेग को बनाए नहीं रखा जा सका। केन्द्र का राजकोषीय घाटा बढ़कर वर्ष 2011-12 में स.घ.उ. का 5.7 प्रतिशत हो गया। (अर्न्तम वास्तविक आंकड़े)। वृहद् आर्थिक परिणाम तथा राजकोषीय परिणाम के बीच संबंध का गत्यात्मक स्वरूप इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ। औद्योगिक उत्पादन में तीव्र मंदी के परिणामस्वरूप समग्र स.घ.उ. की वृद्धि में मंदन आया जिससे कर राजस्व, विशेष रूप से कारपोरेट आयकर प्रभावित हुए जो अब तक का सर्वाधिक उतप्लावक स्रोत हैं; मुद्रास्फीति की निरंतरता के कारण मांग को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हुई एक कठोर मौद्रिक नीति स्थिति ने भी निवेश को मंदित किया; आयोजनाबद्ध विनिवेश कार्यक्रम को बाधित करने

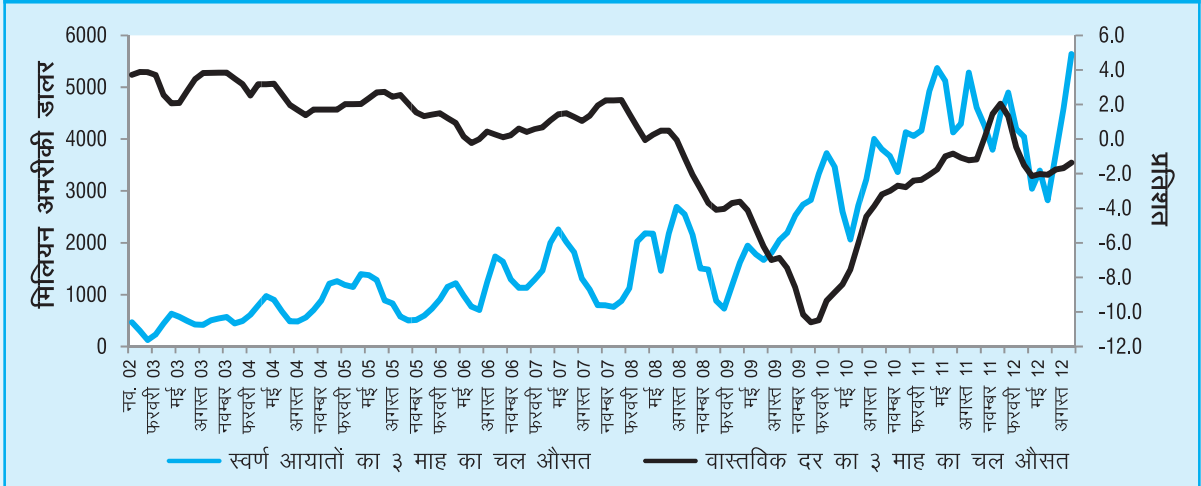
**सारणी 1.6 : चालू खाता शेष**

मद	2011-12 छ1(अप्रैल-सितम्बर 2011)	2012-13 छ1(अप्रैल-सितम्बर 2012)
<b>यूएस \$ बिलियन</b>		
निर्यात	158.2	146.5
आयात	247.7	237.2
व्यापार घाटा	89.5	90.7
निवल अदृश्य प्राप्तियां	53.1	51.7
सीएडी	36.4	39.0
<b>स.घ.उ. के अनुपात के रूप में ज्ञापन मंदें</b>		
व्यापार घाटा	9.9	10.8
निवल अदृश्य प्राप्तियां	5.9	6.2
सीएडी	4.0	4.6

**बॉक्स 1.2 : स्वर्ण का भरमार**

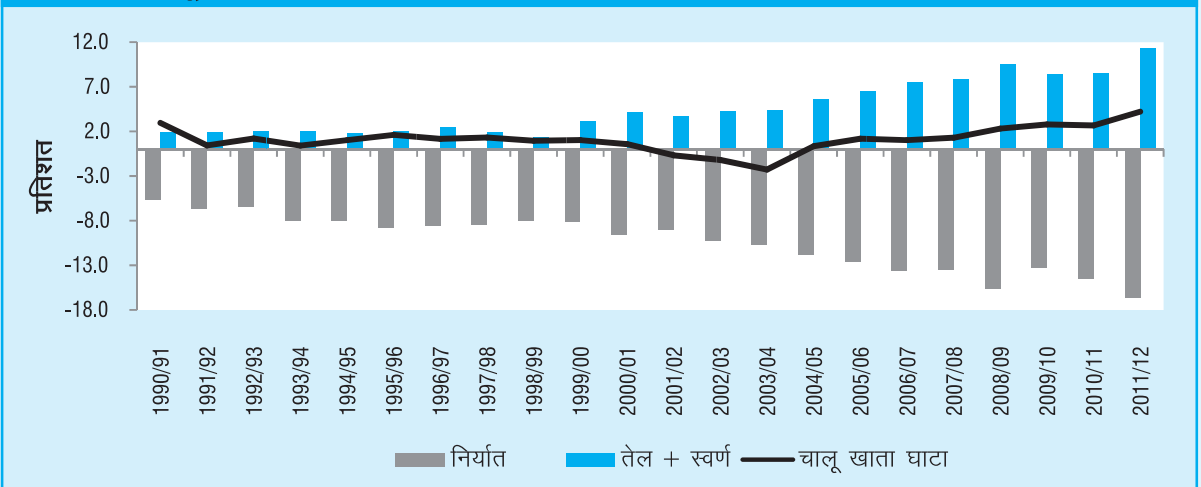
1. **स्वर्ण की मांग में विश्वव्यापी बढ़ोतरी हो रही है:** ऋण संकट बने वैश्विक वित्तीय संकट में वस्तु मूल्यों विशेष कर सोने के मूल्य में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हुई है। पृष्ठ अवलोकन करने पर यह नितांक गैर आश्चर्यजनक तथ्य अधिकांशतः विश्व के बचत निवेशित/संग्रहित करने के लिए सुरक्षित स्थलों की बढ़ती मांग द्वारा प्रेरित रहा है। अमरीकी डालर में मूल्यवर्गित वैश्विक स्वर्ण मूल्य वर्ष 2008 के पश्चात् दोगुने हो गए हैं तथा भारतीय रुपए में मूल्यवर्गित इस की कीमत तीन गुणा हो गई है।
2. **भारत पारम्परिक रूप से वैश्विक स्वर्ण का प्रमुख समावेशन रहा है:** विगत तीन वर्षों में स्वर्ण आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि परिलक्षित हुई है (स्वर्ण आयातों का मूल्य जनवरी 2008 तथा अक्टूबर 2012 के बीच नौ गुणा बढ़ गया है) जिसने तेल के साथ मिल कर चालू खाता घाटे के महत्वपूर्ण योगदान दिया है (चित्र 2)।
3. **स्वर्ण आयातों का मुद्रास्फीति के साथ घनात्मक सह संबंध है:** उच्च मुद्रा स्फीति वित्तीय प्रपत्रों पर प्रतिफल को घटा देती है। यह बढ़ते आयातों तथा कम होती वास्तविक दरों के बीच ऋणात्मक सहसंबंध में परिलक्षित होता है (चित्र 1)। यद्यपि वास्तविक दरों का बढ़ाना शुरू हो गया है, वे मुश्किल में घनात्मक तेजी के अंतर्गत हैं।

**चित्र 1: स्वर्ण आयात (मिलियन अमरीकी डालर) तथा वास्तविक ब्याज दर (रिपो दर-सीपीआई मुद्रास्फीति)**



स्रोत : सीईआईसी डाटा कम्पनी

**चित्र 2: चालू खाते के संघटक स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में**



स्रोत : सीईआईसी डाटा कम्पनी

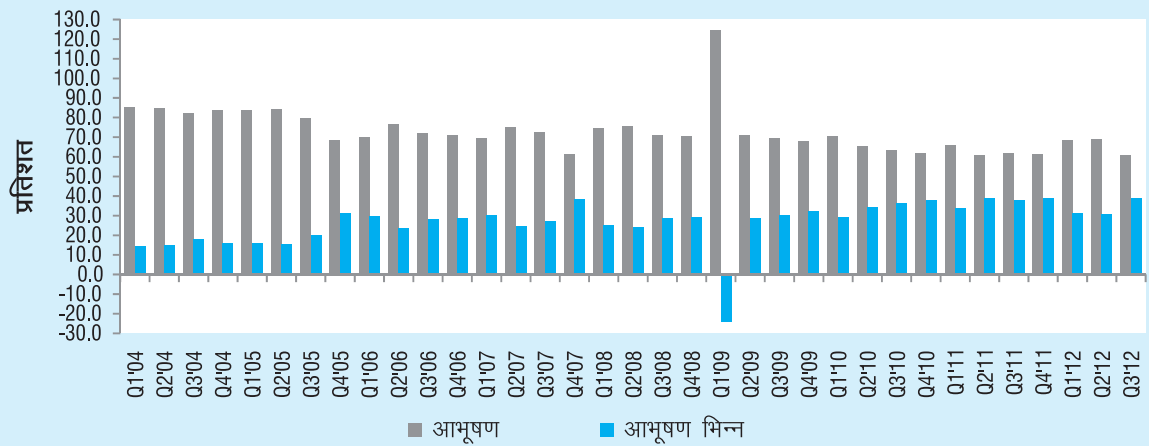
( जारी... )

**बॉक्स 1.2 : स्वर्ण का भरमार ( जारी... )**

4. **चालू खाता घाटा कम करने के लिए स्वर्ण मूल्य कम करना:** बढ़ती ऊर्जा तथा परिवहन आवश्यकताओं को देखते हुए चूंकि हमारे पास तेल आयातों को नियंत्रित करने की बहुत कम संभावना है, स्वर्ण को एक ऐसा संघटक माना जा रहा है जिसे सीएडी को वापस सुखद स्तर पर लाने के लिए नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।

5. **निवेश साधन के रूप में स्वर्ण की मांग समय के साथ साथ बढ़ रही है:** भारत में सोना निवेश माध्यम तथा प्रास्थिति चिह्न का संयोजन है। वित्तीय प्रपत्रों तक विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र में सीमित पहुंच होने के कारण, सोना तथा चांदी लोकप्रिय बचत प्रपत्र हैं। हालिया आर्थिक अनिश्चितता में सर्वत्र लोग स्वर्ण का संचयन कर रहे हैं भारत की अपरिष्कृत सोने की लगभग सम्पूर्ण मांग की पूर्ति आयातों द्वारा की जाती है।<sup>2</sup> चित्र 2 में दर्शाया गया है कि स्वर्ण के संघटन में आभूषण भिन्न मदों की ओर सुस्थिर संचलन हुआ है; अन्य शब्दों में इस की व्याख्या प्रबल रूप से शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में विशुद्ध निवेश के लिए बढ़ती मांग के रूप में की जा सकती है। विगत तिमाही में, आभूषण भिन्न स्वर्ण कुल मांग का 40 प्रतिशत था। वैश्विक रुझानों के समनुरूप इस अवलोकन का कारण निवेशक के लिए उपलब्ध प्रपत्र समूहों पर घटते वास्तविक प्रतिफलों तथा स्वर्ण पर बढ़ते प्रतिफलों को माना जा सकता है (निफ्टी पर 7.3% प्रतिफल तथा बचत जमाराशियों पर 8.2% की तुलना में स्वर्ण पर अप्रैल 07 तक तथा मार्च 2012 के बीच औसतन 23.7% वार्षिक औसत प्रतिफल; सेहगल एवं अन्य, 2012)

**चित्र 3: स्वर्ण मांग का संघटन- आभूषण बनाम अन्य आभूषण**



स्रोत : विश्व स्वर्ण परिषद्

6. **स्वर्ण की बढ़ती मांग को नियंत्रित करने का दीर्घावधिक रास्ता:** स्वर्ण भरमार के पीछे अंतर्हित महत्वपूर्ण उद्देश्य परंपरा के लिए संग्रहण, उच्च मुद्रास्फीति तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिक को उपलब्ध वित्तीय प्रपत्रों का अभाव है। स्वर्ण के लिए बढ़ती मांग अर्थव्यवस्था में अधिक मूलभूत समस्याओं का आज एक 'लक्षण' है। मुद्रास्फीति को रोकना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, मुद्रास्फीति सूचकांकित बांडों जैसे नए उत्पादों की पेशकश करना तथा वित्तीय उत्पादों तक बचतकर्ता अभिगम में सुधार लाना, ये सब अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

1. श्री रोहित लाम्बा तथा डा० प्राची मिश्र द्वारा तैयार हम विश्व स्वर्ण परिषद में अमरेश आचार्य, पीएमईएसी में सुरेश फडनीस, तथा आई एम बी में स्नेहा अरोड़ा तथा अरुण नरेन्द्रनाथ का अनेक चर्चाओं के लिए धन्यवाद करना चाहेंगे।
2. हमारे पास केवल तीन सक्रिय स्वर्ण खाने हैं जो घरेलू मांग के 1% से कम की पूर्ति करती हैं।

**संदर्भ**

सेहगल, संजय मुनीष कुमार, वसीम अहमद तथा प्रियांशी गुप्ता, 2012 "दि गोल्ड रश तथा पालिसी आप्शन्स: एन इम्पीरिकल स्टडी", वित्तीय अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

वाले मंदित वित्तीय बाजार बजट अनुमानों की तुलना में कमी में परिणामी हुए; तथा घरेलू खपत में अपर्याप्त पास थ्रू के साथ कच्चे तेल तथा उर्वरकों की वैश्विक कीमतों के सतत् उच्च स्तर बजटीय व्यवस्था की गई आर्थिक सहायता की तुलना में उच्चतर व्यय में परिणामी हुए। इस प्रकार, वर्ष 2011-12 में राजकोषीय घाटे में चूक राजस्व प्राप्तियों में 35 प्रतिशत की कमी, विनिवेश प्राप्तियों तथा ऋण वसूली में 23 प्रतिशत की कमी तथा व्यय में 42 प्रतिशत की कमी से परिणामित हुई।

1.33 ये वृहद आर्थिक घटनाक्रम मोटे तौर पर चालू राजकोषीय वर्ष के प्रथमार्ध में जारी रहे। अनेक क्षेत्रों से लगातार दूसरे वर्ष राजकोषीय स्थिति के ह्रास तथा राजकोषीय नीति की स्थिति की विश्वसनीयता के बारे में चिंताएं उठाई गईं। यह मानते हुए कि बजट निर्माण के समय लगाए गए कुछ अनुमानों की समीक्षा की जानी तथा सुधारात्मक नीतिगत उपाय सुव्यवस्थित किए जाने आवश्यक है, सरकार ने राजकोषीय समेकन के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने हेतु डा. विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

1.34 इस की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने अक्टूबर 2012 में एक संशोधित राजकोषीय समेकन कार्ययोजना को अनाहत्त किया। इसने 2013-14 के लिए स.घ.उ. के 4.8 प्रतिशत राजकोषीय घाटे तथा तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष 0.6 प्रतिशतांक बिन्दु के सुधार के जरिए 2016-17 में स.घ.उ. के 3.0 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा। पैट्रोलियम उत्पादों, विशेषकर डीजल तथा तरल पैट्रोलियम गैस (एलपीजी) की घरेलू कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवृत्त कीमतों के समनुरूप बढ़ाया जाना आवश्यक है। डीजल की कीमत को बढ़ाने के लिए सितम्बर 2012 में लिए गए निर्णय तथा पुनः जनवरी 2013 में तेल विपणन कम्पनियों को नियमित अंतरालों पर लघु वृद्धियों में कीमत बढ़ाने की अनुमति देने के निर्णय के साथ एक शुरुआत पहले ही की जा चुकी है। आर्थिक सहायता प्राप्त गैस सिलेंडरों की संख्या को भी नौ पर सीमित कर दिया गया है। आर्थिक सहायता को बेहतर लक्ष्यीकरण के जरिए नियंत्रित करने (गैस सिलेंडरों पर उच्चतम सीमा निर्धारित करने के लिए तर्काधार संबंधी बॉक्स 1.3 को देखें), अन्य व्यय को सीमित करने, तथा समय के साथ राजस्व जुटाने के प्रयास भी किए जाने होंगे ताकि राजस्व-स.घ.उ. अनुपात को 2007-08 के स्तरों पर ले जाया जा सके। विनिवेश प्रक्रिया को भी त्वरित किया गया है। इन सभी उपायों को ध्यान में रखते हुए, मध्य वर्षीय आर्थिक समीक्षा 2012-13 में चालू राजकोषीय वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे में संभावित चूक केवल 0.2 प्रतिशत बिंदु होना निर्दिष्ट किया गया है।

1.35 वर्ष 2012-13 के बजट में 5,13,590 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान लगाया गया है। लेखा महानियंत्रक द्वारा उपलब्ध कराए गए केन्द्र सरकार के वित्त साधनों संबंधी आंकड़ों के अनुसार, राजकोषीय घाटा ब.अ. का 78.8 प्रतिशत आंका गया है जो 85.9 प्रतिशत के पंचवर्षीय औसत तथा 92.3 प्रतिशत के विगत वर्ष के स्तर से महत्वपूर्ण रूप से कम है। इसी समय राजकोषीय घाटा ब.अ. का 85.1 प्रतिशत आंका गया है जो हालिया विगत में हासिल स्तर से काफी कम है। ऐसा अधिकांशतः कुल व्यय वृद्धि में संतुलन द्वारा संभव किया गया है जो 2012-13 के लिए 14.8 प्रतिशत के ब.अ. की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 2012 में 10.6 प्रतिशत था (2011-12 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना में)। वृद्धि, में यह संतुलन इस तथ्य के बावजूद है कि अप्रैल-दिसम्बर 2012 में आर्थिक सहायता अत्यधिक बढ़कर 1,66,824 करोड़ रुपए (ब.अ. का 92.9 प्रतिशत) के आंकड़े पर पहुंच गई। व्यय नियंत्रण अप्रैल-दिसम्बर 2012 में ऋण-भिन्न प्राप्तियों के निम्नतर स्तरों को अधिकांशतः प्रतिसंतुलित कर सका।

1.36 सकल कर राजस्व के 2012-13 के लिए 10,77,612 करोड़ रुपए होने की बजटीय व्यवस्था की गई थी। ब.अ. के अनुपात के रूप में, अप्रैल-दिसम्बर 2012 में सकल कर राजस्व 63.2 प्रतिशत था जो 69.0 प्रतिशत के विगत पंचवर्षीय औसत से कम है। अप्रैल-दिसम्बर 2012 में सकल कर राजस्व में वृद्धि 15.0 प्रतिशत थी जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों में 17.4 प्रतिशत,

सीमाशुल्क में 6 प्रतिशत, वैयक्तिक आय कर में 22.5 प्रतिशत, सेवा कर में 33 प्रतिशत तथा कारपोरेट आय कर में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि सन्निहित है।

1.37 2011-12 के अनंतिम वास्तविक आंकड़ों की तुलना में ब.अ. 2012-13 द्वारा परिकल्पित अंतर्हित वर्षानुवर्ष वृद्धि के अर्थ में, चालू राजकोषीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों में कारपोरेट आय कर में 4.9 प्रतिशतांक बिन्दुओं, सीमाशुल्क में 18.9 प्रतिशतांक बिन्दुओं तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में 16 प्रतिशतांक बिन्दुओं की कमी हुई। सेवाकर संग्रहण में 5.9 प्रतिशतांक बिन्दुओं का तथा वैयक्तिक आयकर में 7.6 प्रतिशतांक बिन्दुओं का अतिनिष्पादन हुआ है। समग्र सकल कर राजस्व के अर्थ में अप्रैल-दिसम्बर 2012 में 6 प्रतिशतांक बिन्दुओं की कमी हुई है। इसके बाद चौथी तिमाही में वसूली से ब.अ. की तुलना में वर्ष के लिए कमी की सीमा का निर्धारण होगा।

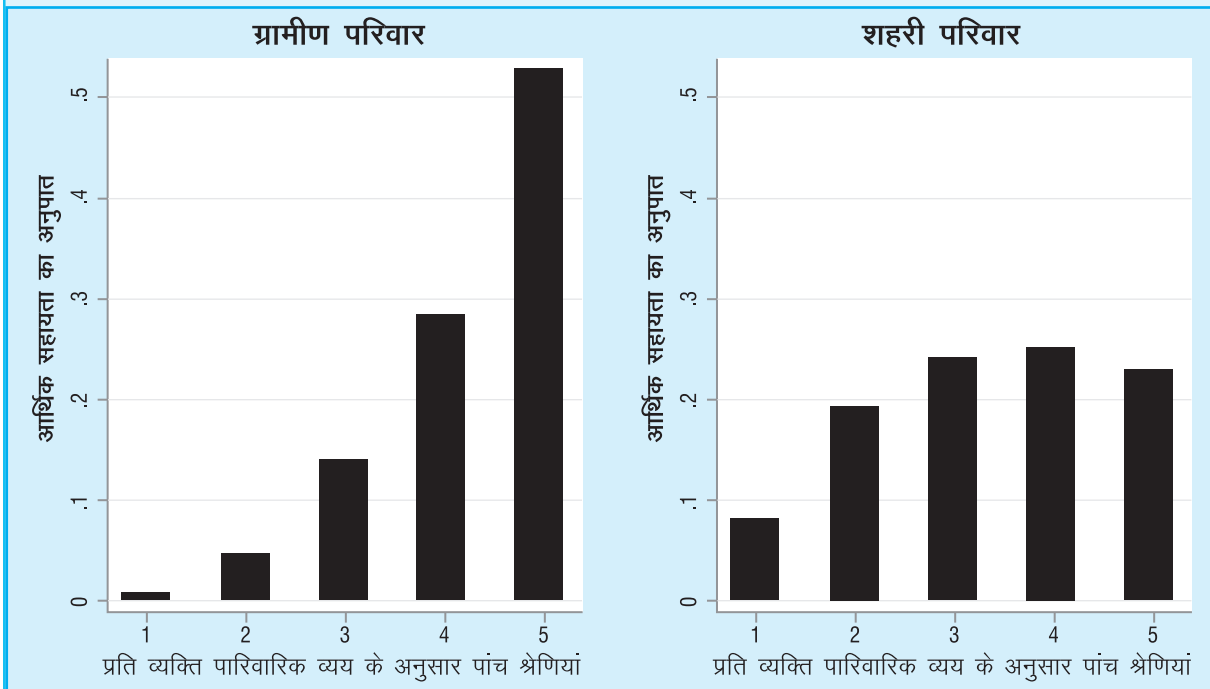
1.38 केन्द्र के राजकोषीय घाटे के अर्थ में परिणाम मोटे तौर पर निर्दिष्ट करता है कि कमी को 0.2 प्रतिशत बिन्दु तक व्यय उपायों के कारण सीमित रखा जाएगा जो ऋण भिन्न प्राप्तियों में कमी को प्रतिसंतुलित करने में सहायता कर सकते हैं। 2011-12 तथा 2012-13 में राजकोषीय परिणाम से उद्भूत महत्वपूर्ण पाठ यह है कि अत्यधिक अनिश्चितताओं के काल में, सन्निकट अनुवीक्षण के जरिए सतत् जोखिम निर्धारण तथा बेहतर राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति के लिए समुचित उपाय करने की आवश्यकता है। उच्चतम सीमा रहित आर्थिक सहायता जैसी असीमित प्रतिबद्धताएं राजकोषीय विश्वसनीयता के लिए विशेष रूप से समस्यात्मक हैं क्योंकि वे, राजकोषीय लक्ष्य प्राप्तियों को कीमतों की उच्छृंखलता में उलझा देती हैं।

1.39 काफी पूरी न हुई विकास आवश्यकताओं के संदर्भ में राजकोषीय समेकन को मात्र स.घ.उ. अनुपात के व्यय में कमी के माध्यम से प्राप्त करने की बजाय उच्चतर कर-स.घ.उ. के माध्यम से प्राप्त करना बेहतर है। 2007-08 में 11.9 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के पश्च, कर स.घ.उ. दर 2009-10 में गिरकर 9.6 प्रतिशत पर आ गई तथा 2011-12 में 9.9 प्रतिशत पर निर्धारित की गई। इसलिए, कर-संघऽऽ अनुपात को 11 प्रतिशत से अधिक करना लम्बे समय के लिए राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में, सांकेतिक कर दरों को महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाने की बजाये उस आधार को जिस पर कर लगाया जाता है को व्यापक करके उच्चतर कर-संघऽऽ अनुपात प्राप्त करना अधिक बेहतर है- उच्चतर और उच्चतर कर दरें, जबकि कर अपवचन को प्रोत्साहित करके, कर योग्य गतिविधियों को करने के प्रेरणास्रोतों पर अधिक और अधिक अतिक्रमण करती है।

1.40 अंत में, उच्चतर राजकोषीय घाटे सामान्यतः लोक ऋण में वृद्धि को जन्म देती हैं। भारत की केन्द्र सरकार देयताएं- संघऽऽ अनुपात वास्तव में 2002-03 से कम हुआ है क्योंकि उच्च सांकेतिक संघऽऽ वृद्धि ने नए उधारों के अलावा सांकेतिक ब्याज

**बॉक्स 1.3 : एलपीजी सब्सिडियां कौन प्राप्त करता है?**

सब्सिडियां गरीबों पर भली-भांति लक्षित होनी चाहिए। एलपीजी पर सब्सिडियों की पहुंच में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों तथा अमीरों के बीच उच्च रूप से असमानता है। बंटवारा शहरी परिवारों के बीच अधिक न्यायसंगत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक गरीब तथा सर्वाधिक धनी परिवारों द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडियों के अनुपात में महत्वपूर्ण असमानता है। तथापि, दोनों मामलों में, गरीबों को दी जाने वाली सब्सिडियों का अनुपात कम है।



ग्रामीण तथा शहरी परिवारों के बीच प्रत्येक पांच श्रेणियों द्वारा प्राप्त की गई एलपीजी सब्सिडियों का अनुपात परिवारों के बीच सब्सिडियों के बंटवारे की गणना के लिए, हम एनएसएस के 64वें दौर का डाटा प्रयोग करते हैं तथा सभी ग्रामीण (तथा शहरी) परिवारों को उनके प्रति व्यक्ति पारिवारिक व्यय के आधार पर पांच श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। इसके अलावा, हम एलपीजी पर कुल व्यय में प्रत्येक पांच श्रेणियों के भाग की गणना के लिए एलपीजी पर सूचित किये गए पारिवारिक व्यय का प्रयोग करते हैं।

उपर्युक्त ग्राफ से, हम ग्रामीण परिवारों के बीच सब्सिडियों के बंटवारे में उच्च स्तरीय असमानता पाते हैं। सब्सिडियों का अनुपात जो सर्वाधिक गरीब पांच श्रेणियों को जाता है, सर्वाधिक अमीर पांच श्रेणियों को जाने वाले 52.6 प्रतिशत की तुलना में केवल 0.7 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में, यद्यपि गरीबों को मिलने वाली सब्सिडियों का अनुपात अभी भी काफी कम है (लगभग 8.2 प्रतिशत), शेष पांच श्रेणियों के बीच अधिक न्यायसंगत बंटवारा है (क्रमशः 19 प्रतिशत, 24 प्रतिशत, 25 प्रतिशत और 23 प्रतिशत)।

\*अभिजीत बैनर्जी तथा गौरव चिपलूकर द्वारा तैयार किया गया।

भुगतानों जिनकी मांग ऋणधारकों ने की, दोनों को प्रतिसंतुलित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, उच्च मुद्रा-स्फीति ने प्रदर्शित किया है। कि उधारों की 'वास्तविक' दरें कम हुई हैं। अन्य शब्दों में, भारत कम वास्तविक ब्याज दरों पर उधार लेने में समर्थ हुआ है जबकि सरकार को राजकोषीय घाटा हुआ है। परिणामों की ऐसी श्रृंखला पर आश्रित नहीं रहा जा सकता यद्यपि जो राजकोषीय घाटे को कम करने का अन्य कारण है।

1.41 लोक वित्त पोषणों में कमी को खोजने का अन्य तरीका है—इसे घरेलू बचतों के प्रसंग में देखना, जो वित्तीय निवेश का सबसे सुरक्षित तरीका है। बड़े राजकोषीय घाटे न्यूनतर लोक बचतों, न्यूनतर घरेलू बचतों, और निवेश का स्तर तय कर, बृहत्तर चालू खाता घाटों को प्रदर्शित कर सकती है। वास्तव में, लोक बचतों में

कमी को पूरा करने के लिए निजी बचतों को बढ़ाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश, 2008-09 और 2009-10 में उर्ध्वमुखी संचलन के पश्चात निजी बचतें लोक बचतों में अवनति की संयोजकता करके, तेजी से गिर गईं।

### घरेलू बचतें

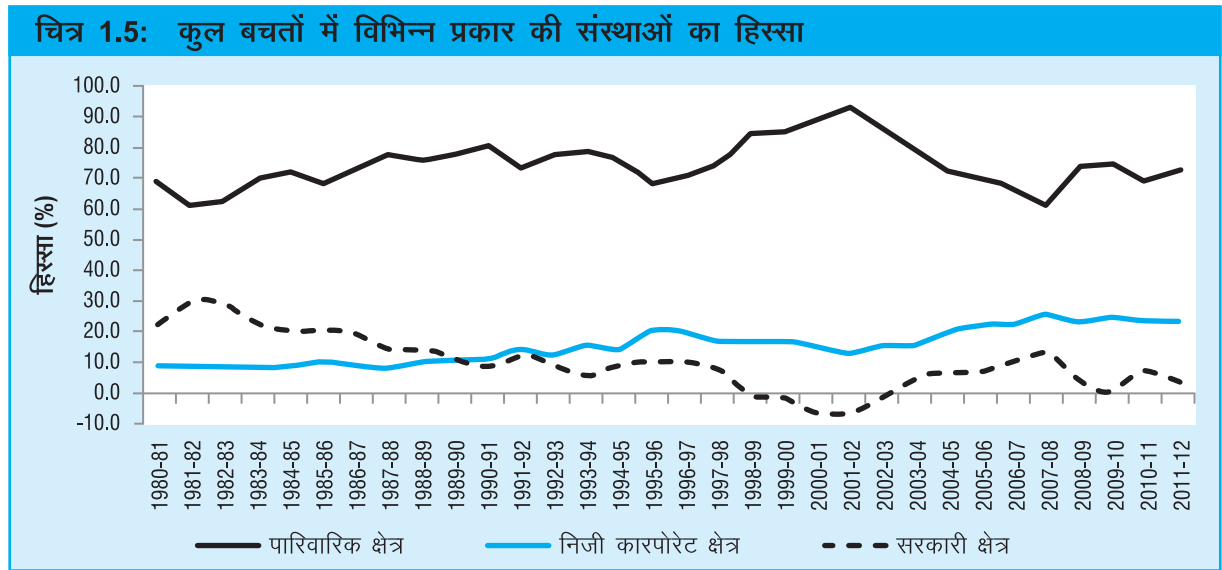
1.42 भारत में घरेलू बचतों का भाग तथा संयोजन में विगत वर्षों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। बचत दर (बाजार मूल्यों पर सघण्ड के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू बचतें) 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में औसतन 18.6 प्रतिशत और 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में 23 प्रतिशत रही। बचत दर पहली बार 2004-5

में 30 प्रतिशत से ऊपर रही तथा हमेशा उस स्तर से ऊपर बनी रही। यह 2007-8 में 36.8 प्रतिशत पर शीर्ष पर थी तथा पिछले 8 वर्षों के सबसे कम स्तर पर 2011-12 (नवीनतम अवधि जिसके लिए हमारे पास पूर्ण आंकड़े हैं) में 30.8 प्रतिशत पर रही (सारणी 1.7)।

1.43 बचतें तीन स्रोतों नामतः घरेलू, निजी कंपनी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र से की जाती हैं। औसत रूप में गृहस्थ कुल घरेलू बचतों के लगभग तीन चौथाई भाग 1980-81 से 2011-12 की अवधि में बचते थे। यह हिस्सा हालिया वर्षों और 2004-5 से 2011-12 तक की अवधि में थोड़ा नीचे आया इसका औसत कुल बचतों का 70.1 प्रतिशत था। निजी कंपनी क्षेत्र की बचतें 1980-81 और 2011-12 के बीच कुल बचतों के औसतन 15 प्रतिशत के हिसाब में थीं। तथापि, वर्ष 2004-5 से 2011-12 की अवधि में उनका हिस्सा 23.2 प्रतिशत तक बढ़ गया। सार्वजनिक क्षेत्र का औसतन हिस्सा 1980-81 और 2011-12 के बीच कुल बचतों का

10 प्रतिशत था। यह उत्तरोत्तर रूप से घटता रहा है और 2004-5 से 2011-12 के दौरान कुल बचतों के अनुपात के रूप में सार्वजनिक बचतों का औसत 6.7 प्रतिशत था। चित्र 1.5 1980-81 से कुल बचतों में घरबार, निजी कंपनी और सार्वजनिक क्षेत्र के अंशदान की प्रवृत्तियां दर्शाता है।

1.44 परिवारों में वास्तविक बचतों की तुलना में वित्तीय बचतों का हिस्सा हालिया वर्षों में घटता रहा है। वित्तीय बचतें बैंक जमा राशियों, जीवन बीमा निधियों, पेंशन और भविष्य निधियों शेयरों और ऋणपत्रों आदि के रूप में की जाती हैं। वित्तीय बचतें 1990 के दशक के दौरान कुल घरबार बचतों के लगभग 55 प्रतिशत के हिसाब में थीं। उनका हिस्सा 2000-1 के दशक में घटकर 47 प्रतिशत रह गया और यह 2011-12 में 36 प्रतिशत था। दरअसल, घरेलू वित्तीय बचतें 2010-11 की तुलना में 2011-12 में लगभग 90,000 करोड़ रुपए तक अल्प थीं। वित्तीय बचतों के हिस्से में गिरावट की चंद संभव व्याख्याएं बाक्स 1.4 में चर्चित हैं।



**सारणी 1.7 : स.घ.उ. की तुलना में बचतों का अनुपात (चालू बाजार कीमतों पर प्रतिशत)**

	2004-05	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 <sup>2स</sup>	2011-12 <sup>1स</sup>
सकल घरेलू बचतें	32.4	34.6	36.8	32.0	33.7	34.0	30.8
सरकारी क्षेत्र	2.3	3.6	5.0	1.0	0.2	2.6	1.3
निजी क्षेत्र	30.1	31.0	31.8	31.1	33.5	31.5	29.5
पारिवारिक क्षेत्र	23.6	23.2	22.4	23.6	25.2	23.5	22.3
वित्तीय बचत	10.1	11.3	11.6	10.1	12.0	10.4	8.0
भौतिक परिसंपत्तियों में बचत	13.4	11.9	10.8	13.5	13.2	13.1	14.3
निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	6.6	7.9	9.4	7.4	8.4	7.9	7.2

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

टिप्पणी : 1स: प्रथम संशोधित अनुमान, 2स: द्वितीय संशोधित अनुमान,

**बॉक्स 1.4 : वित्तीय बचतों में ह्रास**

घरेलू क्षेत्र की अधिक वित्तीय बचतें बैंक जमा (2000 के दशक में लगभग 30 प्रतिशत), जीवन बीमा कोष (1980 के दशक में 9.6 प्रतिशत के मुकाबले में 2000 के दशक में 22 प्रतिशत), और पेंशन तथा भविष्य निधियों (1980 के दशक में 23.6 प्रतिशत के मुकाबले में 2000 के दशक में 16.5 प्रतिशत) के रूप में हैं। विशेषकर 1990 के हालिया दशक से पेंशन और भविष्य निधियों के अनुपात में गिरावट रही है यह रुझान 2007-08 तक जारी रहा। ये ऐसे वर्ष में जब ब्याज की असल दर आम तौर पर गिर रही थी। 2008-09 और 2009-10 के दौरान पेंशन और भविष्य निधियों में कुछ उध्वगति उन सरकारी कर्मचारियों की निपटान योग्य आय में बढ़त के आशिक कारण से रही है जो छोटे वेतन आयोग की अनुशंशाओं के लागू होने के परिणामस्वरूप उच्चतर वेतन और बकाया राशियों की वजह से इन निधियों में उल्लेखनीय अंशदाता है।

शेयर और ऋण पत्र 1980 के दशक में कुल वित्तीय बचतों के 8.3 प्रतिशत के हिसाब में थे; उनका शेयर 2000 के दशक में 4.8 प्रतिशक तक घटने से पूर्व 1990 के दशक में लगभग 13 प्रतिशत तक बढ़ गया। ऐसे रुझान के कारण शेयर कीमतों के व्यवहार हो सकते हैं जो बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेन्सेक्स द्वारा प्रतिबिम्बित तथा निम्नतम सारणी में प्रदर्शित हैं-

	1980s	1990s	2000s
बीएसई सेन्सेक्स का औसत	448	3120	8612
सीएजीआर बीएसई सेन्सेक्स 42 प्रतिशत	-	21.4	10.7
अंतर का गुणांक	42.3	33.2	60.1

**टिप्पणी:** ये आंकड़े आरबीआई की हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकॉनामी में प्राप्त सूचना से परिकलित हैं।

1990 के दशक में कुल वित्तीय बचतों में शेयरों और ऋण पत्रों के अनुपात में वृद्धि का श्रेय अल्पतर अस्थिरता के साथ उच्चतर प्रतिलाभ (इस दशक के औसत पर 21.4 प्रतिशत प्रति वर्ष) दिया जा सकता है। जैसाकि 1980 के दशक में 42.3 से घटकर 1990 के दशक में 33.2 रह गए अल्प अंतर के गुणांक से प्रतिबिम्बित हैं। बीएसई सेन्सेक्स में प्रतिलाभ 2000 के दशक में आधा होकर 10.7 प्रतिशत रह गया और अस्थिरता बढ़ गई जो 60.1 पर अंतर गुणांक के उच्चतर मूल्य से दृष्टतम हैं इस प्रकार 1990 के दशक की तुलना में 2000 के दशक में अल्पतर प्रतिलाभ और उच्चतर अस्थिरता के संयोजन का परिणाम कुल वित्तीय बचतों में शेयरों और ऋणपत्रों का हासित अंश हो सकता है। उच्च मुद्रास्फीति के प्रभाव से यह हालिया दिनों में स्वर्ण के सुरक्षित निवेश मद बन चुकने का एक कारण हो सकता है। बॉक्स 1 और 7.2 देखें) देश में गृहस्थों द्वारा स्वर्ण के अर्जन से बचतों और घरेलू वित्त निवेश पर नकारात्मक असर पड़ने की प्रवृत्ति रहती है।

1.45 कुल बचतों में निजी कंपनी क्षेत्र के वर्धमान हिस्से का एक कारण यह हो सकता है कि उत्पादन अनुपात के लिए कुल लाभ में वृद्धि 1980 के दशक में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर 1990 के दशक में 5.4 प्रतिशत और फैक्टरी क्षेत्र में 2000 के दशक में इससे आगे 7.9 प्रतिशत तक बढ़ गई वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण से प्राप्त सूचानुसार अनुमानित। कतिपय लागतों अर्थात् परिलब्धियों; ब्याज संदाय और कुल उत्पादन मूल्य के अनुपात के रूप में ईंधन में गिरावट भी रही है जिसे सारणी 1.8 से समझा जा सकता है। इस गिरावट के परिणामस्वरूप लाभ और इसके बाद कंपनी क्षेत्र में उच्च बचतें हुई हैं।

1.46 उद्योग क्षेत्र में मंदी का प्रभाव निजी कंपनी बचतों पर पड़ा है जैसेकि 2008-09 में और फिर 2011-12 में स्थिति थी, और इस प्रकार की बचतों का पुनरुत्थान इस पर निर्भर करता है कि उद्योग में कितनी तेजी से सुधार आता है।

1.47 सरकारी क्षेत्रक बचतों में निम्न द्वारा बचतें शामिल हैं:-  
(क) सरकारी प्राधिकरण जिनमें सरकारी प्रशासन तथा अर्ध सरकारी निकाय तथा विभागीय वाणिज्यिक उद्यम शामिल हैं तथा  
(ख) गैर-विभागीय वाणिज्यिक उद्यम। कुल बचतों में सरकारी बचतों का हिस्सा प्रगामी रूप से कम होकर 1980 के दशक में

20 प्रतिशत से अधिक के स्तर से कम होकर 1990 के दशक में 7.3 प्रतिशत रह गया तथा 2000 के दशक में और कम होकर 3.3 प्रतिशत रह गया। सरकारी बचतों के अंतर्गत, गैर विभागीय सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों का हिस्सा तीन उप अवधियों में से प्रत्येक के दौरान औसतन 12-13 प्रतिशत की सीमा में बना रहा। कुल बचतों में सरकारी प्राधिकरणों का हिस्सा 1980 के दशक में 7.4 प्रतिशत के योगदान में लगभग 16 प्रतिशतांक बिन्दु घटकर 2000 के दशक में 8.7 प्रतिशत का ऋणात्मक योगदान रह गया। वर्ष 1987-88 से सरकारी प्राधिकरण सामान्यता व्यय कर्ता रहे हैं जिनके 1998-99 से भारी खर्चे हो रहे हैं।

1.48 सरकारी प्राधिकरणों द्वारा बचतों में गिरावट के दीर्घकालिक रुझान के बावजूद सुधार की अवधियां भी रही हैं। राजस्व में सशक्त वृद्धि तथा 2003 के राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के आधार पर, केन्द्र तथा राज्य सरकार, दोनों का संयुक्त राजकोषीय घाटा 2002-03 में स.घ.उ. के 9.6 प्रतिशत से घटकर 2007-08 में स.घ.उ. का 4 प्रतिशत रह गया। स.घ.उ. के अनुपात के रूप में सरकारी क्षेत्रक बचतें 2002-03 में स.घ.उ. के -0.3 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में .5 प्रतिशत हो गए जिसके पश्चात् ये 2008-09 में राजकोषीय प्रेरण के अनुसरण में पुनः



**सारणी 1.8 : उत्पादन मूल्य के अनुपात के रूप में कतिपय निवेशों की लागत ( प्रतिशत )**

	1980s	1990s	2000s
कुल परिलब्धियां	9.2	6.7	4.3
ईंधन लागत	8.3	7.4	6.7
भुगतान किया गया ब्याज	5.1	5.5	2.6
उपभोग किया गया सामान	60.8	59.4	62.2

स्रोत : उद्योग, फैक्टरी क्षेत्र के वार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित।

हासित हो गई। वर्ष 2003-04 तथा 2007-08 के बीच घरेलू बचत दर में महत्वपूर्ण सुधार का काल काफी अधिक सीमा तक राजकोषीय समेकन से उद्भूत वर्धित सरकारी बचतों को माना जा सकता है।

1.49 जैसाकि सारणी 1.5 से पता चलता है। सकल नियत पूंजी निर्माण में 2007-08 की पूर्व संकट अवधि तथा 2011-12 के बीच लगभग 3 प्रतिशतांक बिन्दुओं की गिरावट आई है। तथापि, इसी अवधि में सकल घरेलू बचतें लगभग 6 प्रतिशतांक बिन्दु कम हुई हैं। इस प्रकार जबकि हमें निवेश विशेषकर कारपोरेट निवेश को बढ़ाना है। घरेलू बचतों को बढ़ाना चालू खाता अधिशेष पर दबाव डाले बिना वृद्धि का वित्तपोषण करने का सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग है। बचतों में भावी वृद्धि का एक बड़ा भाग वर्धित सरकारी बचतों से प्राप्त होता है। इसमें केन्द्र सरकार के राजकोषीय घाटे को 2011-12 में 5.8 प्रतिशत से क्रमिक रूप से कम कर राजकोषीय कार्य योजना के अनुसार 2016-17 के लिए अनुमानित 3 प्रतिशत पर लाना है (ब्यौरों के लिए पूर्ववर्ती संभाग को देखें)।

1.50 पारिवारिक बचतों को भी बढ़ाया जाना होगा। पारिवारिक क्षेत्र की वित्तीय बचतों में निम्नतर मुद्रास्फीति से सुधार आने की संभावना है विशेषकर तब जब वित्तीय बचतों पर प्रतिफल की वास्तविक दर में वृद्धि होगी। विश्वसनीय वित्तीय बचत अवसरों (जैसे मुद्रास्फीति सूचकांकित बांड) की अपेक्षाकृत अधिक विविधता तथा उन तक पहुंच की सापेक्ष सहजता भी स्वर्ण जैसे विकल्पों की आकर्षणीयता को कम कर कुल बचतों में वित्तीय बचतों के हिस्से को बढ़ाने में सहायक हो सकती है।

1.51 आइए अब हम वृहद् आर्थिक असंतुलनों के दो महत्वपूर्ण परिणामों पर नजर डालें-कीमतें तथा भुगतान संतुलन या विदेशी स्थिति।

### कीमतें तथा मौद्रिक प्रबंधन

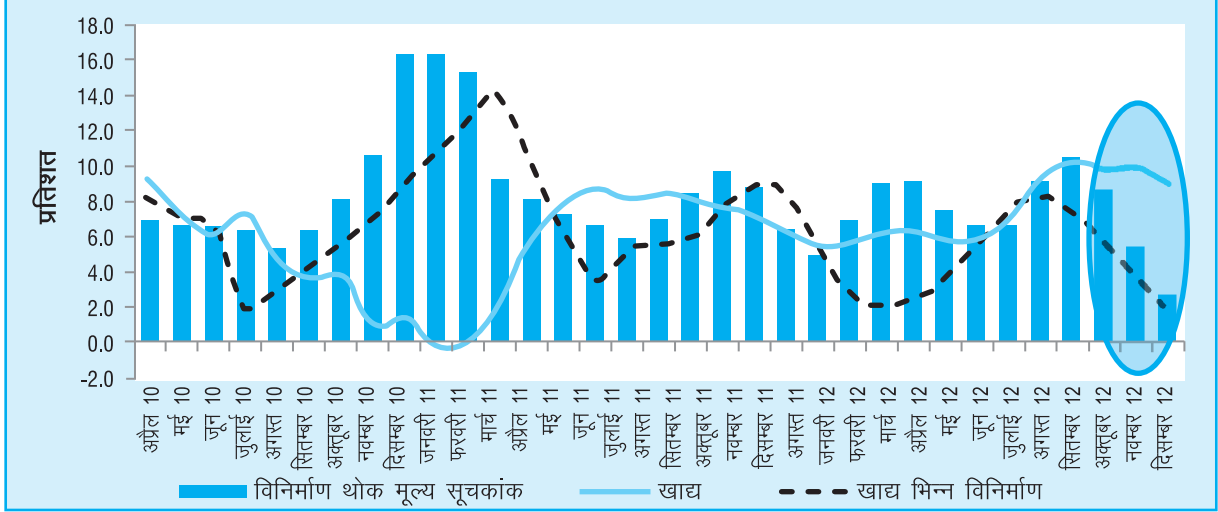
1.52 प्रमुख थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 7 से 8 प्रतिशत पर सापेक्षतया स्थिर बनी रही तथा दिसम्बर, 2012 में संतुलित होकर 7.18 प्रतिशत के तीन वर्षीय

निम्न स्तर पर पहुंच गई। 2012 (अप्रैल-दिसम्बर) में औसत प्रमुख थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति विगत वर्ष की तदनुसूची अवधि में 9.35 प्रतिशत से घटकर 7.55 प्रतिशत हो गई। मौसमी रूप से समायोजित वार्षिकीकृत दर (एमएएआर) पर आधारित संवेग भी विगत कुछ माहों में थोक मूल्य सूचकांक के प्रमुख उपसमूहों के लिए एक हासकारी रुझान प्रदर्शित कर रहा है (चित्र 1.6)। यह गिरावट मुख्यतः खाद्य भिन्न विनिर्माण मुद्रास्फीति (भा.रि.बैंक द्वारा यथा परिभाषित मूल मुद्रास्फीति) में संतुलन के कारण है। मूल मुद्रास्फीति मंद रही तथा नवम्बर 2011 में 8.35 प्रतिशत के अपने चरण स्तर से घटकर दिसम्बर 2012 में 4.24 प्रतिशत रह गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक उपायों के अलावा, रसायनों तथा वस्त्र उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू कीमतों के कम होने से भी मूल मुद्रास्फीति के संतुलन में योगदान दिया।

1.53 तथापि, दिसम्बर 2012 में क्रमिक रूप से द्विअंकीय स्तर की ओर बढ़ती मुद्रास्फीति के साथ बढ़ी हुई खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है। विगत वर्ष के विपरीत जन खाद्य मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की उच्चतर कीमतों का होना था, इस वर्ष यह दबाव मुख्यतः अनाज से आ रहा है। आनाजों में मुद्रास्फीति 2012-13 की प्रथम तिमाही में 6.36 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 की तीसरी तिमाही में 17.05 प्रतिशत हो गई जिसका मुख्य कारण गेहूं चावल तथा मक्का कीमतों में वृद्धि का होना है। इस के अतिरिक्त, गेहूं तथा चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि, मांग के सापेक्ष विशेषकर गेहूं की अपर्याप्त मुक्त बाजार उपलब्धता भी अनाजों के मूल्यदबाव के निर्माण तथा मुद्रास्फीति के बढ़ने में परिणामी हुई है। दिसम्बर 2012-जनवरी 2013 में प्याज की कीमतों में हालिया वृद्धि का भी प्राथमिक खाद्य मदों की मुद्रास्फीति पर कुछ दबाव पड़ेगा। तथापि 2012-13 की द्वितीय तथा तीसरी तिमाही में दूध तथा अन्य प्रोटीन मदों में संतुलन परिलक्षित हुआ।

1.54 बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति ने सीपीआई तथा डब्ल्यूपीआई के अर्थ में मापित मुद्रास्फीति के बीच अंतर को मई 2012 में 1.55 प्रतिशतांक बिन्दु से बढ़ाकर दिसम्बर 2012 में 3.91 प्रतिशतांक बिन्दु कर दिया है। तथापि, हालिया समय तक ऊर्जा तथा ऊर्जा भिन्न, दोनों कीमतों में गिरावट दर्ज होने से वैश्विक वस्तु मूल्य सापेक्षतया तक मृदु बने रहे। विश्व बैंक के ग्लोबल इकानामिक प्रास्पेक्ट के अनुसार, घातुओं को छोड़कर अधिकांश वस्तु कीमतों में 2013 तथा 2014 में आगे और गिरावट आने की आशा है जो धीमे वैश्विक सुधार में एक सुनहरी रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से मृदु मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं के प्रभाव का घरेलू कीमतों पर एक संतुलनकारी प्रभाव पड़ेगा।

चित्र 1.6: थोक मूल्य संचकांक के प्रमुख उप समूहों में संवेग (एसएएआर)



1.55 इस दौरान, यद्यपि भारतीय रिजर्व बैंक को तेजी से कम होती लागतों की तुलना निरंतर कायम सीपीआई मुद्रास्फीति के साथ करती है, उस सीमा तक जहां तक सीपीआई मुद्रास्फीति का प्राथमिक संघटक खाद्य पदार्थ हैं, कीमतों में आपूर्ति बाधाओं के कारण वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के लिए पाठ्यपुस्तक मार्ग दर्शन निर्धारित करते समय उच्चतर खाद्य कीमतों पर ध्यान देने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल मुद्रास्फीति में यथा प्रतिबिम्बित द्वितीय दौर प्रभाव' नियंत्रित किए जाए। अन्य शब्दों में उसे मूल मुद्रास्फीति के व्यवहार के आधार पर मौद्रिक नीति नियत करनी है। इस अधिक समायोजन दृष्टिकोण में एक समस्या यह है कि सीपीआई मुद्रास्फीति, जिसपर जनता नजर रखती है, जनता की प्रत्याशाओं में निराशाजनक बनती जा रही है। एक दूसरी चिंता यह है कि उच्च मुद्रास्फीति के कारण चिंतित निवेशक जमाराशियां जैसे नियत आय निवेशों का परिहार करेंगे तथा मुद्रास्फीति सुरक्षा के रूप में स्वर्ण का सहारा लेंगे। जिससे सीएडी बढ़ेगा। तथापि, उस सीमा तक जहां तक मौद्रिक नीति का मुद्रास्फीति के कतिपय पहलुओं पर सीमित प्रभाव है जैसे खाद्य कीमतें, मौद्रिक नीति के लिए यह समुचित होगा कि दरों का निर्धारण इसके प्रभाव क्षेत्र को ध्यान में रख कर किया जाए तथा साथ ही यह ध्यान में रखा जाए कि सांकेतिक ब्याज दरें, वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के अलावा अर्थव्यवस्था के अनेक पहलुओं को प्रभावित करती है।

1.56 सरकार के परिदृश्य से, मुद्रास्फीति के विरुद्ध संघर्ष में एक प्रमुख योगदान मांग के लिए राजकोषीय प्रेरण को कम करना होगा। साथ ही भंडारण और तिरण को सुकर बनाने के साथ-साथ कीमत सहायता को छोड़ कर अन्य उपायों के जरिए खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन देने पर सकेन्द्रण भी खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता कर सकता है जिसे नियंत्रित करना भारतीय रिजर्व बैंक के लिए कठिन है। कीमत तथा अधिप्राप्ति सहायता संबंधी नीति को अशाकित करना होगा ताकि अधिक उत्पादन को प्रोत्साहित ना किया जाए। निवेश को अधिक व्यापक रूप से बढ़ाने

के अन्य उपाय और इस प्रकार आपूर्ति भी मध्यावधि में सहायक हो सकती है।

### भुगतान संतुलन तथा विदेशी स्थिति

1.57 वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध में चालू खाता घाटा स.घ.उ. का 4.6 प्रतिशत रहा है। उपलब्ध संकेत द्वितीयार्ध में चालू खाता शेष में किसी महत्वपूर्ण सुधार का निर्दिष्ट करते प्रतीत नहीं होते। स्वर्ण जैसे वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने तथा निर्यात बढ़ाने के प्रयास करने का एक तर्काधार है। हालांकि सरकार ने आयातों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वर्ण पर प्रशुल्क को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने के द्वारा चक्रगति को धीमा किया है तथा स्वर्ण ऋणों के जरिए अक्रिय स्वर्ण धारिताओं को मुक्त करने का प्रयास किया है। स्वर्ण क्रय में प्रमुखतः कमी तभी आने की संभावनाओं है जब परिवारों को आकर्षक वैकल्पिक निवेश मार्ग दिखाई दें। इसकी कुंजी निम्नतर मुद्रास्फीति होगी। इस दौरान, वर्तमान संयोजन पर निर्यातों को बढ़ाना वैश्विक सुधार की धीमी गति को देखते हुए एक अधिक कठिन कार्य सिद्ध हो रहा है। अपेक्षाकृत अधिक उत्पादकता के साथ-साथ बेहतर सभार तंत्र अवसंरचना के माध्यम से निर्यातों की अधिक प्रतिस्पर्धात्मकता से सहायता मिलेगी तथा साथ ही तीव्र वृद्धिकारी उदीयमान तथा अग्रवर्ती बाजारों में विविधीकरण भी सहायक होगा। यह कार्य किया जा रहा है। किन्तु विगत सशक्त निर्यात वृद्धि की ओर वापसी औद्योगिक देशों में वृद्धि के पुनरुज्जीवन पर निर्भर करेगी।

1.58 निवल निर्यात कम हाने के साथ भारत का भुगतान संतुलन दबावग्रस्त हो गया है। अभी तक सीएडी का वित्तपोषण आरक्षित भंडारों से आहरण के बिना वित्तपोषित किया गया है। निवल पूंजी प्रवाह 2011-12 के प्रथमार्ध में 43.5 बिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ.) का 4.8 प्रतिशत) की तुलना में कम होकर 2012-13

**सारणी 1.9 : बीओपी का निष्पादन**

मदें	2011-12 छ1(अप्रैल सित. 2011)	2012-13 छ1(अप्रैल - सित. 2012)
	<b>यूएस \$ बिलियन</b>	
सीएडी	36.4	39.0
पूँजी खाता	43.5	40.0
निवल एफडीआई	15.7	12.8
निवल पोर्टफोलियो (एफआईआई सहित)	1.3	5.8
अनिवासी जमा राशियां	3.9	9.4
ईसीबी	8.4	1.7
व्यापार ऋण	5.9	9.5
<b>संघट्ट के प्रतिशत के रूप में ज्ञापन मदें</b>		
सीएडी	4.0	4.6
निवल पूँजी प्रवाह	4.8	4.8

टिप्पणी : ईसीबी विदेशी वाणिज्यिक उधार रकमें है।

के प्रथमार्ध में 40.0 बिलियन अमरीकी डालर (स.घ.उ. का 4.8 प्रतिशत) रह गए (सारणी 1.9)। भारत के निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) घट गए हैं किन्तु विदेशी संस्थागत निवेशों (एफआईआई) सहित निवल पोर्टफोलियो प्रवाह बढ़े हैं तथा आरम्भिक अनुमान सुझाते हैं कि द्वितीय तिमाही में 5.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में तृतीय तिमाही में 9.9 बिलियन अमरीकी डालर का ओर भी अधिक अंतर्वाह हो गया। अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियां मजबूत बनी रहीं तथा साथ ही व्यापार ऋण के निवल प्रवाह भी मजबूत बने रहे। विशाल सीएडी के बावजूद इसी कारण वर्ष 2012-13 के प्रथमार्ध के दौरान आरक्षित भंडारों में (भुगतान संतुलन आधार पर; 0.4 बिलियन अमरीकी डालर की निवल वृद्धि हुई। फिर भी यह विगत वर्ष के प्रथमार्ध में 5.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में निम्नतर थी।

1.59 वर्तमान राजकोषीय वर्ष में, विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार 286.0 बिलियन अमरीकी डालर तथा 295.6 बिलियन अमरीकी

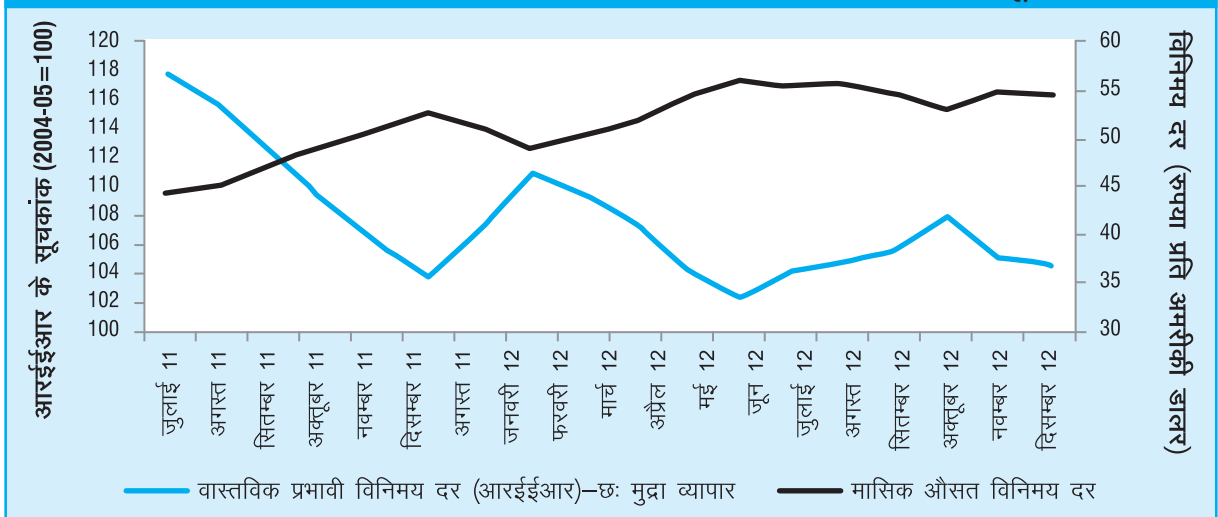
डालर के नीचे घटते बढ़ते रहे। जनवरी 2013 के अंत में, प्रारक्षित भंडारों की राशि 295.5 बिलियन अमरीकी डालर थी जो मार्चांत 2012 में 294.4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में मामूल सी वृद्धि को निर्दिष्ट करते हैं। तथापि रुपया अधिक अस्थिर रहा है। अप्रैल 2012 तथा जनवरी 2013 के बीच प्रति अमरीकी डालर रुपए का मासिक औसत मूल्य अत्यधिक अस्थिर रहा तथा यह 27 जून 2012 को 57.22 रुपए प्रति अमरीकी डालर के अब तक के सर्वाधिक निम्न स्तर पर पहुंच गया जिससे रुपए के मूल्य में 30 मार्च 2012 को 51.16 रुपए प्रति अमरीकी डालर की तुलना में 10.6 प्रतिशत का अवमूल्यन हुआ। जुलाई से सितम्बर 2012 के अनुवर्ती माहों में, रुपए का मूल्य बढ़ा और 5 अक्टूबर 2012 को यह 51.62 रुपए प्रति डालर था। तत्पश्चात् इसका पुनः अवमूल्यन होना शुरू हुआ तथा तब से अक्टूबर 2012 से जनवरी 2013 के दौरान यह 53.02 रुपए से 54.76 रुपए प्रति अमरीकी डालर के बीच रहा (चित्र 1.7)।

1.60 भारत में घरेलू मुद्रास्फीति को ध्यान में रखने वाली वास्तविक प्रभावी विनियम दर, जो भारतीय निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है। 2011 की मध्यावधि से लगभग 11 प्रतिशत हासित हुई है।

1.61 भारत का विदेशी ऋण स्टॉक सितम्बर, 2012 के अंत में 365.3 बिलियन अमरीकी डालर था जो मार्चांत 2012 के स्तर की तुलना में लगभग 20.0 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि (5.8 प्रतिशत) दर्ज करता है। यह वृद्धि प्रमुखतः उच्चतर एनआरआई जमाराशियां, अल्पावधि ऋण तथा ईसीबी के कारण हुई है। इन तीन संघटकों ने इकट्ठे मिलकर देश के विदेशी ऋण की कुल वृद्धि में 94.7 प्रतिशत का योगदान दिया।

1.62 भारत के विदेशी ऋण के परिपक्वता पार्श्वचित्र में दीर्घावधिक ऋणों की प्रबलता जारी रही है। सितम्बर 2012 के अंत में, 280.8 बिलियन अमरीकी डालर पर दीर्घावधिक विदेशी ऋण कुल विदेशी ऋण के 76.9 प्रतिशत के लिए उत्तरदायी था जबकि शेष

**चित्र 1.7: रुपए की प्रति अमरीकी डालर मासिक औसत दर तथा आरईआई के सूचकांक**



23.1 प्रतिशत अल्पावधि ऋण था। सरकार (शासकीय) विदेशी ऋण 81.5 बिलियन अमरीकी डालर था जब कि गैर सरकारी ऋण सितम्बर 2012 के अंत में 283.9 बिलियन अमरीकी डालर था। भारत का विदेशी ऋण नियंत्रणीय सीमाओं में रहा है जैसाकि 2011-12 में 19.7 प्रतिशत के विदेशी ऋण स.घ.उ. अनुपात तथा 6.0 प्रतिशत के ऋण शोधन अनुपात से निर्दिष्ट होता है। किन्तु विदेशी ऋण के आकार, स्रोत, परिपक्वता तथा सुरक्षा के रुझानों का सावधानीपूर्वक अनुवीक्षण किया जाना आवश्यक है। विशेष रूप से, विनियामकों के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जन रहित कुछ भारतीय कम्पनियों या कारपोरेशनों की इस प्रवृत्ति के बारे में सावधान रहना होगा कि वे 'सस्ता' विदेशी वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा उधारों को असंरक्षित छोड़ देते हैं। निम्न असंरक्षित विदेशी ब्याज दरें धोखेपूर्ण ढंग से लुभावनी हो सकती है जिसमें उधारकर्ता की महत्वपूर्ण उच्चतर पुनर्भुगतानों की देनदारी हो जाती है यदि रूपए का अप्रत्याशित रूप से अवमूल्यन हो जाता है।

1.63 इस संदर्भ में, विनियामकों के सार्वजनिक महत्व तथा विवेकसम्पत्ता के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। सार्वजनिक महत्व के क्षेत्रों जैसे अवसंरचना के लिए पर्याप्त सहायता आवश्यक है। तथापि क्रियाकलाप के ये क्षेत्र जोखिमग्रस्त भी हो सकते हैं। यह सहायता क्षेत्रों को जोखिम रहित करके (अवसंरचना परियोजनाओं को त्वरित करने और उनकी पूर्णता को सहज बनाने की नीति), वित्तीय विकास (नई वित्त पोषण संस्थाओं का सृजन करना, नए निवेशकों को आकृष्ट करना) या राजकोषीय माध्यमों (ब्याज सहायता, कर आस्थगत/छूट) के माध्यम में दी जानी चाहिए किन्तु विवेकपूर्ण मानदंडों को शिथिल कर के (निम्नतर पूंजी अपेक्षाएं, आरक्षित उधार की अनुमति देकर), या अधिक जोखिमग्रस्त संरचनाओं (अपेक्षाकृत अधिक ऋण अनुपात अनुमत करके) नहीं दी जानी चाहिए। अंततः, सार्वजनिक महत्व की परियोजनाओं के लिए अधिक जोखिमपूर्ण वित्तपोषण देश के लिए अधिक जोखिमपूर्ण हो जाता है क्योंकि यदि ये परियोजनाएं विफल हो जाती हैं तो वे एक साथ ही ऐसे समय पर संवृद्धि तथा वित्तीय प्रणाली दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं जब सरकार के पास सामना करने के अपेक्षाकृत कम संसाधन होते हैं।

## निर्धारण और नीतिगत उपाय

1.64 भारत के वित्त संकट के बाद जोरदार राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप इस संकट के तत्काल पश्च प्रभाव में दृश्यमान विकास हुआ। परंतु कंपनी और अवसंरचनात्मक निवेश में गति नहीं आने, और खाद्य उत्पादन में रुकावट आने के कारण उपभोग को बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप अंततः मुद्रास्फीति उच्चतर हो गई। और अंशतः सरकारी व्यय के परिणामस्वरूप और अंशतः उच्चतर मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप घटती बचतों की परिणति सीएडी के वृहदाकार होने में हुई है। मौद्रिक नीति कड़ी कर दी गई है, हालांकि संवृद्धि में वैश्विक प्रतिकूलताएं बढ़ गई हैं। भारत गिरती संवृद्धि और प्रोत्साहन हास के दुष्चक्र में फंस गया

है जिससे इस गिरावट में काफी तीव्रता आ सकती है। संवृद्धि के मंद हो चुकने के बावजूद विदेशी उधार पर भारत की वर्धित निर्भरता कुछ चिंताओं में से एक चिंतन है।

1.65 मंदी और उच्च स्तरों के प्रोत्साहन के कारण कुछ उद्योग और अवसंरचना क्षेत्रों में गैरनिष्पादक आस्तियों (एनपीए) में वृद्धि महसूस कर की जा रही है। बैंककारी क्षेत्र का समग्र सकल एनपीए मार्च 2011 में प्रदत्त कुल ऋण के 2.36 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर, 2012 में प्रदत्त कुल ऋण का 3.57 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि खासकर उद्योग और अवसंरचना क्षेत्रों में है। विशेषरूप से दबाव में रहने वाले उपक्षेत्रों में कपड़ा, रसायन, लोहा और इस्पात, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण और दूरसंचार शामिल हैं। सकल एनपीए में वृद्धि सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के लिए उल्लेखनीय रूप से भी उच्चतर है जो आपातग्रस्त क्षेत्रों की ओर विशेष रूप से ज्यादातर मुखातिब हैं।

1.66 एनपीए में वृद्धि के कारणों में से कुछ कारण तकनीकी हैं। (सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों द्वारा प्रणाली आधारित पहचान की ओर अंतरण) परंतु आपात स्थिति मंद विकास और परियोजनागत विलंबों से भी उत्पन्न होती है। संवृद्धि के उत्थान से एनपीए को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, लेकिन प्रबंधन से अप्रभावी संवर्धकों को हटाते हुए और जोखिम लेने की संविदा कर चुके व्यक्तियों पर हानियों को डालते हुए इस पर आगे और अधिक ध्यान दिया जाना होगा कि क्या परियोजनाओं का पूंजीकरण जोखिमों को देखते हुए पर्याप्त रूप से तत्काल किया जाता है और क्या आपात समाधान तंत्र आपदाग्रस्त आस्तियों के पुनः पूंजीकरण और उन्हें फिर से कार्य पर लगाने में कारगर रूप से काम कर रहे हैं।

1.67 लाभप्रद आवर्ती चक्र प्रारंभ करने का उपाय और आशा राष्ट्रीय खर्च को उपभोग से निवेश में ले जाने, आंशिक रूप से संरचनात्मक सुधारों के जरिए निवेश, संवृद्धि और रोजगार सृजन में गत्यवरोधों को दूर करने, मौद्रिक और आपूर्तिपक्षीय दोनों उपायों से मुद्रास्फीति से जूझने, वित्तीयन जुटाने वाले उधारकर्ताओं के लिए लागतें घटाने और भारी वास्तविक निवेश प्रतिलाभ पाने के लिए बचतकर्ताओं हेतु अवसरों को बढ़ाने में निहित है।

1.68 सरकारी नीति के लिए व्यावहारिक दृष्टि से इसका आशय अपव्ययी और भ्रांतिकारी आर्थिक सहायता को खासकर न्यूनतम करके राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना है। इसका अभिप्राय अनुज्ञाएं प्राप्त करने में विलंबों जैसी निवेशगत अड़चनों को कम करना, भूमि अधिग्रहण की कठिन और गैरपारदर्शी प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना और विद्युत तथा सड़क जैसी बेहतर अवसंरचना की सुविधा बढ़ाना है। इसके लिए उस विनियामक और प्रोत्साहन संरचना को फिर से तैयार करने की ज़रूरत है जिससे लघु व्यवसाय बहुत छोटे बने रहते हैं और उन्हें बेहतर लाभप्रद रोजगारों के सृजन में रुकावट होती है। व्यवसाय के विविध क्षेत्रों में घरेलू कंपनियों को वंचित नहीं होने देना भी सुनिश्चित करते हुए प्रवेश की बाधाओं को कम करने तथा

एफडीआई को अनुमति देने की ज़रूरत है। इसके लिए खाद्य प्रापण और वितरण में प्रबंधन और संभार संभारतंत्रों का सुधार करते हुए उत्पादन बढ़ाने हेतु किसानों को प्रोत्साहन और साधन मुहैया कराना परमावश्यक है। इसके लिए नई संस्थाओं का प्रवेश बढ़ाने, निवेशकों की कारोबारी लागतें घटाने, उधार कर्ताओं और बचतकर्ताओं तक एक-दूसरे की पहुंच बढ़ाने और विनियमन की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु अविच्छिन्न वित्तीय क्षेत्रक सुधार करने की आवश्यकता है।

1.69 सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में पहले से ही उठाए हैं जिनमें से कुछ का पूर्व में संकेत किया जा चुका है। इसके अलावा दो संभावित घटनाक्रम एक राजस्व पक्ष का और दूसरा व्यय पक्ष का, दृष्टिपथ में हैं। माल और सेवा कर अनुमोदित किए जाने पर अनेक राज्य और केंद्रीय करों का स्थान लेंगे, भारत को और अधिक राष्ट्रीय समेकित बाजार बनाएंगे, और अधिक उत्पादकों को दर के दायरे में लाएंगे। दक्षता और राजस्वों में सुधार करके यह संवृद्धि में पर्याप्त इजाफे के साथ-साथ सरकारी वित्त साधनों में मदद करा सकता है। व्यय पक्ष पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, जिससे सरकारी व्ययों का अंतरण सीधे लक्षित ग्राही बैंक खातों को करने दिया जाएगा, से कारोबार लागतों को घटाने, दुहरापन, रिसाव और कपट को रोकने, और गरीबों के लिए विकल्पों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अनेक इमदादों को समतुल्य नगदी अंतरणों में बदलकर यह मूल्य की हेराफेरी नहीं होने दे सकता है और इमदादों को दरअसल पात्र लोगों तक बेहतर ढंग से पहुंचा सकता है। इससे व्यय नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

1.70 सरकार ने निवेश और संवृद्धि को पुनरुज्जीवन देने के लिए अनेक उपाय भी किए हैं। इन उपायों में 1000 करोड़ रु. से अधिक की वृहद् परियोजनाओं पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीसीआई का गठन करना; राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के कर्जों की पुनः संरचना योजना, जिसमें तर्कसंगत टैरिफ प्रभारित करने हेतु उनके लिए प्रोत्साहन शामिल है जिससे कि वे फिर से अति कर्ज में न डूब जाएं; भूमि अधिग्रहण विधेयक की ओर संचलन जिससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया स्पष्ट और निष्पक्ष होगी; मल्टीब्रांड फुटकर व्यवसाय, विद्युत केंद्रों और नागर विमानन सहित अनेक क्षेत्रों में एफडीआई को अनुमति देना; सिंचाई, भंडारण और शीत भंडारण नेटवर्कों में निवेश बढ़ाना; और प्रोटीन आहारों के उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम शुरू करना शामिल है।

1.71 वित्त क्षेत्रक सुधार संबंधी उपाय भी किए गए हैं। बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 से आरबीआई की विनियामक शक्तियां मजबूत होती हैं और आरबीआई द्वारा नई बैंक अनुविज्ञापितियां मंजूर करने का मार्ग प्रशस्त होता है। वित्त क्षेत्रक विधायी सुधार आयोग वित्त क्षेत्र के नियंत्रक कानूनों की जांच कर रहा है और उनके आधुनिकीकरण के उपाय सुझाकर भेजता भी है। सरकार ने वित्त क्षेत्रक विनियामकों के साथ अनेक उपाय घरेलू और

बाह्य दोनों निवेशकों के लिए देश में बचतों और निवेश को आसान करने हेतु किए हैं। इनका ब्यौरा अध्याय 5 में दिया गया है।

1.72 अधिक सामान्य रूप से भारत की स्थिति कठिन है किन्तु वृहद् अर्थव्यवस्था को वापस संतुलन पर लाने तथा वृद्धि को ट्रेक पर लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। महत्वपूर्ण यह स्वीकारना है कि काफी कुछ किया जाना आवश्यक है तथा अवमंदन कार्यों तथा सुधारों की गति को बढ़ाने के लिए एक चेतावनी है।

## अल्पावधिक और मध्यावधिक संभावना

1.73 मौद्रिक तथा राजकोषीय मोर्चों पर किए जा रहे उपायों के बावजूद कम से कम निकट भविष्य में प्रगत देशों के वृद्धि का पुनरुत्थान धीमा तथा अनिश्चित होने की आशा है। यूरोप में विशेष रूप से इसके साथ सांस्थानिक ढांचे में परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। चल रहे निजी क्षेत्रक मंदन तथा सरकारी राजकोषीय समेकन के साथ अधिकांश विश्लेषकों ने 2013 में एक अत्यंत संतुलित वैश्विक सुधार का अनुमान लगाया है जिसमें 2014 में तेजी आ सकती है। इसके साथ ही, यदि संयुक्त राज्य अमरीका अपनी राजकोषीय समस्या का सामना कर सकता है तो वैश्विक वृद्धि की ऊर्ध्वमुखी संभाव्यता पर्याप्त हो सकती है जिसका कारण अमरीकी कारपोरेशनों की सुदृढ़ता, सतत नवाचार निम्न ऊर्जा लागतें तथा परिवारों के बेहतर वित्त साधन हैं। उभरते बाजार भी धीमी औद्योगिक क्षेत्रक वृद्धि की थोड़ी सी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं तथा भारतीय निर्यातों की बदलती दिशा से उनके पुनरुत्थान में सहायता मिलेगी (देखें अध्याय 7)

1.74 फिर भी यह असंभावित है कि भारतीय वृद्धि के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था से सहायता महत्वपूर्ण होगी। वस्तुतः अधोमुखी जोखिम के दो स्रोत हैं। प्रथमतः भारत को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की जोखिम सहिष्णुता में अंतरणों का सामना करना पड़ता है। दूसरे, भारत का आयात बिल तेल की कीमत के साथ सुदृढ़तापूर्वक सहबद्ध है। वस्तुतः बढ़ती तेल कीमतों का एक कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार भी होगा जिसका अर्थ होगा अपेक्षाकृत अधिक निर्यात। अधिक चिंताजनक स्थिति यह होगी कि यदि भू-राजनैतिक जोखिमों के कारण तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका अर्थ होगा बढ़ती निवेशक चिन्ता तथा धीमी वैश्विक संवृद्धि।

1.75 वस्तुतः तथ्य यह है कि भारत विदेशी माहौल पर निर्भर नहीं रह सकता तथा उसे घरेलू संतुलन बहाल करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी होगी। सरकार राजकोषीय समेकन के लिए प्रतिबद्ध है। नीतिगत दरें कम करने के लिए भारि. बैं. को अपेक्षित नम्यता प्रदान करते हुए चल रहे मांग संपीड़न तथा वर्धित कृषिय उत्पादन के साथ यह निम्नतर मुद्रास्फीति में परिणामी होगा। निम्नतर ब्याज दरें उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों के लिए

निवेश क्रियाकलाप को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगी, विशेषकर यदि निवेश में विनियामक अधिकारी तंत्रिय तथा वित्तीय बाधाएं कम हो जाती हैं।

1.76 ऐसे परिदृश्य के मद्देनजर, जहां अर्थव्यवस्था के सभी तीन प्रमुख क्षेत्रक 2012-13 की तुलना में 2013-14 में बेहतर निष्पादन करते हैं, समग्र अर्थव्यवस्था के 2013-14 में 6.1 से 6.7 प्रतिशत की सीमा में बढ़ने की आशा है। वस्तुतः इन अनुमानों में यह माना गया है कि मानसून सामान्य होगा, मुदास्फीति आशानुसार आगे और संतुलित होगी (कठोर मौद्रिक स्थिति में और नम्यता अभिप्रेरित करने के लिए) तथा प्रत्याशानुसार वैश्विक वृद्धि में मृदु सुधार होगा। संभावी परिवर्तन बिंदुओं पर पूर्वानुमान लगाना कठिन है अतः इस बार सापेक्षतया व्यापक सीमा है।

1.77 हालांकि वर्तमान माहौल कठिनाई का माहौल है, भविष्य में आशा सन्निहित है बशर्ते कि हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकें जो भारत की युवा आबादी के दिमागों में संभवतः सबसे आगे है: “मुझे नौकरी कहां से मिलेगी?” अध्याय 2 में हमने इस प्रश्न पर कुछ गइराई से विचार किया है। भारत उद्योग में नौकरियों को सृजित कर रहा है, किन्तु ऐसा मुख्यतः निम्न उत्पादकता निर्माण में किया जा रहा है। तथा विनिर्माण में पर्याप्त औपचारिक नौकरियां सृजित नहीं की जा रही जिन में पारम्परिक रूप से उच्च उत्पादकता है। उच्च उत्पादकता सेवा क्षेत्र पर्याप्त नौकरियां सृजित नहीं कर रहा है, जैसे जैसे आबादी के बढ़ने तथा कृषि के संकुचित होने के कारण नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की संख्या बढ़ेगी, ये कमजोरियां अधिक महत्वपूर्ण बन जाएंगी चूंकि अच्छी नौकरियां संवृद्धि के लिए मार्ग पथ तथा समावेशन का सर्वात्तम स्वरूप, दोनों ही हैं हमें उनका सृजन समर्थकारी बनाने के तरीकों पर विचार करना है। अध्याय 2 में संभावित मार्गों/तरीकों की जांच की गई है।

1.78 आइए अब हम समीक्षा में अध्यायों की संक्षिप्त रूपरेखा पर विचार करें जिसका सकेन्द्रण एक जटिल अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा पहलुओं पर है।

## कृषि तथा खाद्य प्रबंधन

1.79 भारतीय कृषि का निष्पादन विगत कुछ वर्षों में मौसम तथा कीमत आघातों के बावजूद उत्पादन की वृद्धि के अर्थ में उल्लेखनीय रहा है। यद्यपि सहबद्ध क्रियाकलापों सहित कृषि का हिस्सा 2011-12 में संघ-उ० का केवल 14.1 प्रतिशत था, 2001 की जनगणना के अनुसार कुल रोजगार में 58.2 प्रतिशत के इसके उच्चारण के साथ देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका कहीं अधिक है। देश के संघ-उ० में कृषि और सहबद्ध क्षेत्र का घटता अंश किसी भी तीव्र वृद्धिशील अर्थव्यवस्था के सामान्य

विकास पथ के सुसंगत है (देखें अध्याय 2) किन्तु तीव्र कृषिय वृद्धि नौकरियों, आय तथा खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है।

1.80 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की औसत वार्षिक वृद्धि 4% लक्ष्य से कम 3.6% रही लेकिन यह नौवीं व दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रमशः 2.5% एवं 2.4% औसत वार्षिक वृद्धि से अधिक थी। कृषि क्षेत्र की गतिकी का महत्वपूर्ण कारण इस क्षेत्र के संघ-उ० के सापेक्ष घरेलू पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में एक कदम आगे होना है। कृषि क्षेत्र (संबद्ध क्षेत्र सहित) में कुल जीसीएफ गत 10 वर्षों में दोगुने से भी अधिक था और इसने 8.1% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की। 11वीं योजना के दौरान, 2009-10 को छोड़कर खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोत्तरी का रुख देखा गया। 2011-12 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन 259.3 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बेहतर प्रदर्शन के निम्न कारण हैं: (क) बेहतर मूल्यों के प्रति किसानों की प्रतिक्रिया (ख) प्रौद्योगिकीय लाभ का जारी रहना, और (ग) उपयुक्त व समय पर नीतिगत एकजुटता, उदाहरणार्थ रियायती दरों पर वर्धित ऋण। तथापि, दक्षिण-पश्चिम मानसून में कमी एवं परिणामस्वरूप उपज की क्षति से 2012-13 में खरीफ फसलों के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। सभी प्रमुख फसलों की उपज में गिरावट की आशंका है।

1.81 हॉल के वर्षों में खाद्यान्नों के अच्छे उत्पादन एवं लाभदायक न्यूनतम बिक्री मूल्यों के कारण पारंपरिक तौर पर खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीद न करने वाले राज्यों यथा बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में काफी बढ़ोत्तरी देखी गई। हाल के वर्षों में, सरकार द्वारा नीतिगत प्रोत्साहन से भी कृषि निर्यात में काफी अपेक्षित स्थिरता आई।

1.82 तथापि, कृषि उपज अथवा उत्पादकता के संबंध में भारत की स्थिति सही नहीं है। भारत के लिए खाद्यान्न में स्वावलंबी बने रहने की कुंजी उत्पादकता में सुधार है। एक अन्य चुनौती है कि अधिक स्थायीवत कृषि कार्यनीति अपनाते समय कृषि आय को अधिकतम किस प्रकार किया जाए। यहां चिंता देश के कुछ भागों में मृदा अपरदन, मृदा लवणता के कारण भूमि व जल निरलीकरण, जलभराव, पोषक तत्वों का अधिकाधिक प्रयोग और जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन हैं। अवनत भूमि एवं जल संसाधनों के पुनर्वास हेतु बेहतर प्रबंधन निधियां इसकी कुंजी हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि अनुसंधान पर व्यय में भी बढ़ोत्तरी किए जाने की जरूरत है।

1.83 भारतीय कृषि क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता छोटे किसानों की प्रमुखता है। इससे फार्म मशीनीकरण एवं फार्म संचालन से अधिक लाभदायक आय सृजित करने की चुनौती उत्पन्न होती है। कृषि क्षेत्र के पुनरुत्थान हेतु भूमि संबंधी मुद्दों एवं भू-सुधारों का कार्यान्वयन प्राथमिक आधार पर किया जाना अपेक्षित है। भारत में एक अन्य चिंता खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में गिरावट है। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में बढ़ोत्तरी करना ही महत्वपूर्ण नहीं है वरन् एक आम आदमी की थाली में मदों की सही मात्रा सुनिश्चित करना भी है। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बागवानी उत्पादों व प्रोटीन समूह मदों पर जोर देना आवश्यक है।

1.84 एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा भारत में कृषि विपणन में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन है। यह आवश्यक है कि हम कृषि उत्पादन गतिविधियों के साथ प्रसंस्करण, लाजिस्टिक और खुदरा बिक्री को जोड़ने के लिए एक तंत्र विकसित करें जिसके लिए वर्तमान कृषि विपणन में स्थायी सुधारों की अपेक्षा है। हाल ही में, सरकार ने खुदरा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को अनुमति दी है जिसका कई किसान संगठनों द्वारा भी समर्थन किया गया है और इससे नई प्रौद्योगिकी और भारत में कृषि उपज के विपणन में निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

1.85 ऐसी स्थायी और भरोसेमंद नीतियों की आवश्यकता है जिनमें बाजारों की उचित भूमिका हो, अवसंरचना में निजी निवेश को बढ़ाया जाए, लोक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को पुनः निर्मित किया जाए, जिससे खाद्य मूल्य और खाद्य भंडार प्रबंधन में सुधार आए एवं कृषि हेतु एक पूर्वानुमेय व्यापार नीति अपनाई जाए इन उपायों में ऋण, बीज आदि की उन्नत डिलीवरी के साथ-साथ कौशल विकास एवं बेहतर अनुसंधान व विकास होना आवश्यक है।

## उद्योग और अवसंरचना

1.86 लगातार दूसरे वर्ष पूंजीगत वस्तु क्षेत्र कमजोर रहा है। पूंजीगत वस्तु प्रदेश उपक्षेत्र में ही ऋणात्मक वृद्धि नहीं रही बल्कि गत 12 माह में केवल दो माह में अधिक सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए अधिक सतत् रहीं। निवेश में कमी, नई परियोजनाओं में गिरावट और आयात में प्रतिस्पर्धा के कारण प्रमुख पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनरी एवं उपकरण, इलेक्ट्रिक मशीनरी और परिवहन क्षेत्र के उत्पादन में कमी आई है। गृहस्थ अथवा खुदरा क्रेडिट में उच्च ब्याज दर व निम्न वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभोक्ता टिकारू वस्तुओं की वृद्धि में कमी आई।

1.87 धीमे औद्योगिक प्रदर्श का प्रभाव कार्पोरेट प्रदर्श पर भी पड़ा। निजी क्षेत्र में सूचीबद्ध विनिर्माता कंपनियों की बिक्री में वृद्धि

दर 2010-11 की पहली तिमाही में 28.0 प्रतिशत से घटकर 2012-13 की दूसरी तिमाही में 11.4 प्रतिशत हो गई। ब्याज व्यय में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई। बिक्री की वृद्धि दर में गिरावट के साथ बिक्री के प्रति निवल लाभ के अनुपात में भी गिरावट आई।

1.88 तथापि, अन्य प्रपत्रों के माध्यम से बैंकों द्वारा संवितरित क्रेडिट और घरेलू व विदेशी बाजार में उगाहे गए धन सहित उद्योग को संसाधन के कुल प्रवाह में आशावादिता के कुछ चिह्न दिखाई दिए। चालू वित्त वर्ष में अभी तक (11 जनवरी 2013 तक) वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह पूर्व वर्ष की समान अवधि की तुलना में उच्चतर रहा है।

1.89 अप्रैल-दिसम्बर 2012 के दौरान 8 मूल अवसंरचना उद्योगों ने पूर्व वर्ष में इसी अवधि के दौरान 4.8 प्रतिशत के मुकाबले 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। चालू वर्ष में अभी तक वृद्धि में गिरावट मुख्यतः कोयले, प्राकृतिक गैस और उर्वरक के उत्पादन में नकारात्मक गिरावट की वजह से है। चालू वर्ष के पहले 8 माह के दौरान अवसंरचना सेवाओं में, रेलवे द्वारा भाड़ा यातायात और बंदरगाहों द्वारा संचालित कारगो अपेक्षाकृत उच्चतर रहे हैं। सड़क के क्षेत्र में, अप्रैल-नवम्बर 2012 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राजमार्गों को चौड़ा और सुदृढ़ करने में 17.3% वृद्धि हासिल की है।

1.90 150 करोड़ व उससे अधिक लागत वाली बहुत सी प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं उनकी नवीनतम समाप्ति तिथि से विलंबित हैं। भू-अधिग्रहण, नगर निगम से अनुमति, ठेका देने, संचालन संबंधी मुद्दों आदि के कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अभी भी विलंब जारी है।

## सेवा क्षेत्र

1.91 विश्व की अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं एवं कुछ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत में सेवा क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र है। वर्ष 2004-05 से 2011-12 की अवधि हेतु सेवा क्षेत्र के स.घ.उ. का सीएजीआर 10% था। स्पष्ट रूप से इसमें उद्योग व कृषि क्षेत्र से अधिक वृद्धि हुई है। 2011-12 और 2012-13 में अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी के अनुरूप सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर में भी गिरावट आई है। सेवा क्षेत्र अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है लेकिन यह देखते हुए कि उत्पादक सेवा रोजगार कैसे हैं, (अध्याय 2 देखें), रोजगार वृद्धि संभवतः वांछित गति से कम है।

1.92 विगत 6 वर्षों की दो अंकीय वृद्धि से 2011-12 और विशेषकर 2012-13 में सेवाओं में वृद्धि दर में मंदी का अर्थव्यवस्था में कुल वृद्धि की मंदी में काफी योगदान रहा है। हालांकि कुछ मंदी कृषि और औद्योगिक गतिविधियों में कम वृद्धि के कारण हो सकती

है, सेवाओं के पश्च तथा अग्र संबंधनों के कारण इसमें शेष दुनिया से मांग में कमी की भी भूमिका हो सकती है।

### वित्तीय मध्यस्थता

1.93 वास्तविक आर्थिक वृद्धि हासिल करने के लिए सु-विकसित एवं कुशल वित्तीय बाजारों की विद्यमान होना महत्वपूर्ण होता है। देश में अज बाजार कुशलता, पारदर्शिता एवं मूल्य अन्वेषण प्रक्रिया के संदर्भ में उत्साहशील और पारदर्शी वित्तीय बाजार है।

1.94 जहां तक बैंकिंग क्षेत्र का संबंध है, फोक्स सुधार संबंधी उपायों पर जारी है जिससे कृषि, अवसंरचना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, हाऊसिंग व निर्यात सहित अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को क्रेडिट के प्रवाह में सुविधा होगी। वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग अवसंरचना की उन्नत पहुंच सरकार की प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर रही। वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय बैंकों के प्रदर्शन में वैश्विक वित्तीय बाजारों के कमजोर सुधार के साथ-साथ लगातार उच्च मुद्रास्फीति एवं मंद वृद्धि प्रदर्शन युक्त घरेलू मोर्चे पर चुनौतीपूर्ण संचालन वातावरण द्वारा काफी हद तक अनुकूलन हुआ। बैंकों की निवल लाभ वृद्धि में मंदी आई। यद्यपि भारतीय बैंक सु-पूँजीकृत रहें, बढ़ती एनपीए के संबंध में चिंता जारी है।

1.96 देश और वैश्विक वित्तीय घटनाओं में व्यष्टि अर्थव्यवस्था की स्थिति के विकास के संदर्भ में, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के साथ घनिष्ठ सहयोग अर्थव्यवस्था की बढ़ती पूँजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कई उपाय किए हैं। इस संबंध में भारतीय पूँजीगत बाजार तक उनकी पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना (आजीईएसएस) और एसएमई एक्सचेंज/प्लेटफार्म, अर्हक विदेशी निवेशक योजना का विस्तार, विभिन्न ऋण श्रेणियों में एफआईआई हेतु परिमाणात्मक सीमा में प्रगामी वृद्धि, भारतीय कंपनियों हेतु विद्युत क्षेत्र में ईसीबी रूट के जरिये रुपये के ऋण को पुनः वित्तपोषण और विनिर्माण व अवसंरचना क्षेत्र में कंपनियों हेतु नई ईसीबी योजना शुरू करना है।

1.96 सामान्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विशेषकर बाजारों में विदेशी निवेशकों के अधिक विश्वास से गत कुछ माह में निवेशकों की भावनाओं में सुधार आने लगा है। चालू वित्त वर्ष (31 दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान, सेंसेक्स का सूचकांक 11.62% और निफ्टी का सूचकांक 11.51% था। यूरोजोन क्षेत्र और संयुक्त राज्य में आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रम का भारत सहित विश्वभर के बाजारों पर प्रभाव पड़ा है। संयुक्त राज्य में वित्तीय कगार के अस्थायी समाधान का बाजारों पर

सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा हाल ही में किए गए सुधारात्मक उपायों को बाजारों ने सहर्ष स्वीकार किया है।

### मानव विकास

1.97 हालांकि आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण होती है किंतु यह स्वयं में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। बारहवीं पंचवर्षीय योजना, 'तीव्रतर, समावेशी व स्थायीवत वृद्धि' पर फोकस के साथ, वृद्धि संबंधी बहस को सही परिदृश्य प्रदान करती है। सरकार की गरीबों के लिए कमतर लीकेज संभावनाओं वाली लक्षित नीतियों से परिव्ययों से बेहतर परिणाम प्राप्ति में मदद मिल सकती है।

1.98 सामान्य सरकार (केंद्र व राज्य, संयुक्त) द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय में हॉल के वर्षों में गिरावट देखी गई है जो इस क्षेत्र को दी गई उच्च प्राथमिकता को प्रतिबिंबित करता है। 12वीं योजना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है, जिसमें शिक्षा क्षेत्र का अंश सर्वाधिक है जिसके बाद स्वास्थ्य की बारी आती है। स.घ.उ. के अनुपात के तौर पर, समाजिक सेवाओं पर व्यय 2007-8 में 5.9% से बढ़कर 2010-11 में 6.8% और इसके बाद 2012-13 (ब.अ.) में बढ़कर 7.1% हो गया है। तथापि, स.घ.उ. के % के रूप में स्वास्थ्य पर भारत का व्यय कई अन्य उभरते व विकसित देशों से कम है और सरकारी क्षेत्र का अंश अभी भी कम है।

1.100 देश में गरीबी में गिरावट आई है, यद्यपि वर्तमान में इसकी जांच की जा रही है कि गरीबी का मापन कितनी सटीकता से किया जाता है। तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाई गई विधि के आधार पर, देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों का प्रतिशत 2004-5 में 37.2% से घटकर 2009-10 में 29.8% रह गया है। समग्र रूप में भी, इस अवधि के दौरान गरीब लोगों की संख्या में 52.4 मिलियन की गिरावट आई है। इसमें से, 48.1 मिलियन ग्रामीण गरीब और 4.3 मिलियन शहरी गरीब हैं। इस प्रकार 2004-5 और 2009-10 के बीच प्रतिवर्ष 1.5% औसत के हिसाब से गरीबी में गिरावट आई है। 2004-5 में 2009-10 के दौरान गिरावट की वार्षिक दर 1993-4 से 2004-5 की अवधि से दोगुनी रही है।

1.100 गत कुछ वर्षों में, सामाजिक कार्यक्रमों में सरकारी व्यय में नाटकीय बढ़ोतरी हुई है। 11वीं योजनावधि में, 15 प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर लगभग रू. 7 लाख करोड़ का व्यय किया गया है। जनता के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु कई वैधानिक उपाय किए गए हैं जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), वन अधिकार अधिनियम तथा शिक्षा का अधिकार। तथापि, कुछ प्रशासन संबंधी दबाव वाले मुद्दे भी हैं जैसे कार्यक्रम लीकेज और



धनराशि का लक्षित लाभार्थियों को न मिलना जिसका समाधान किए जाने की जरूरत है। यूनिवर्सल आईडेन्टीफिकेशन (यूआईडी) संख्या की मदद से प्रत्यक्ष नकद अंतरण (डीलीटी) इन लीकेज में से कुछ को कम कर सकता है।

## सम्पोषणीय विकास और जलवायु परिवर्तन

1.101 यद्यपि, सम्पोषणीय विकास और जलवायु परिवर्तन पर बहु-आयामी प्रयासों से कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, अभी भी चिंता के ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए और अधिक कार्य किए जाने की जरूरत है। इसमें समाधान हेतु प्रमुख प्रश्न विकसित व्यवस्था में इक्विटी है। यहां सुनिश्चित किया जाना है कि घरेलू लक्ष्यों का राष्ट्रीय तौर पर निर्धारण होता रहे चाहे हम सीबीडीआर के सिद्धांत के अनुसार, वैश्विक प्रयासों में सहयोग करें। अधिक महत्वपूर्ण है कि वैश्विक पर्यावरणीय संसाधनों तक इक्विटी, उचित भार साझेदारी और समान

पहुंच को सुरक्षित किया जाए और अधिक उचित तौर पर उनका समाधान किया जाए।

1.102 12वीं योजना में “पर्यावरणीय सम्पोषणीयता” पर फोकस के साथ, भारत सही राह पर है। तथापि, भारत के लिए वृद्धि के प्रमुख प्रेरकों और समर्थकारकों को चाहे यह अवसंरचना, परिवहन क्षेत्र, हाऊसिंग, अथवा स्थायीवत् कृषि हो, पर्याप्त वृद्धिकारी बनाने की चुनौती है। इससे हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे; अधिक सम्पोषणीय आर्थिक वृद्धि हेतु आवश्यकता पूरी करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना पर आते हैं। अधिकतर, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अवरोध संसाधनों की कमी होती है। हालांकि यहां मूल्य सूचकों एवं अन्य नीतिगत मुद्दों को कम करने हेतु कुशल व तत्काल प्रयास किए जाते हैं, भारत इससे अधिक कर सकता है यदि बहुआयामी प्रक्रियाओं के माध्यम से नई व अतिरिक्त वित्त व प्रौद्योगिकी मुहैया कराए जाएं। विकासशील देशों के लिए अधिक सहयोग, कार्रवाई और नवप्रवर्तन, वित्त व प्रौद्योगिकी के प्रावधान और क्षमता निर्माण हेतु संस्थाओं व यंत्रों के लिए तर्काधार है।